श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

Now, I move to the next issue which is Short Duration Discussion. If there are new Ministers and new Members, they should be aware of this Rule. Balasubramoniyanji. ...*(Interruptions)*... Mr. Balasubramoniyan, please. ...*(Interruptions)*... Please . ...*(Interruptions)*... Whoever wants to leave, quietly, they can stand and then quietly withdraw from the Lobby. This is the practice. Shri Sanjay Singh. कहां हैं श्री संजय सिंह? One minute. The total time allotted for this subject is ' Two Hour Thirty Minutes' . The Minister has to reply. Keeping that in mind, I am apportioning the time among the Members who have given notice first and then if time remains, others also will get an opportunity. Sanjayji ...*(Interruptions)*... It is a very, very serious issue. Please pay attention.

SHORT DURATION DISCUSSTTION

The challenges of water crisis including the supply of drinking water in the country

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पानी के संकट पर, जो आज एक राष्ट्रीय संकट के रूप में इस पूरे देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है, उस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।

महोदय, अगर पानी के संकट की बात करें, तो स्थिति यह है कि कहां से बात शुरू की जाए और कहां खत्म की जाए?

(श्री उपसभापति *पीठासीन हुए)*

महोदय, इंडिया टुडे ने अभी दो अंक पहले अपनी मैगज़ीन का पूरा अंक देश के जल संकट पर समर्पित किया था और बताया था कि किस तरह से पूरे राष्ट्र के अंदर पानी की समस्या, खास तौर से पीने के पानी की समस्या, सिंचाई के पानी की समस्या, तालाबों की समस्या, वह चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, जहां पर ...**(व्यवधान)**... सर, हाउस ऑर्डर में करा दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखिए। संजय जी बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... हम उनसे कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, वह चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जहां पर केंद्र की सरकार भी रहती है और हमारे राज्य की भी सरकार है, वहां पर जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। हम लोग सरकार में आए थे, तब उस वक्त ऐसी स्थितियां थीं कि 55 प्रतिशत दिल्लीवासियों को पीने का पानी नसीब होता था। आज लगभग साढ़े चार, पांच सालों का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह संख्या 88 प्रतिशत है। हम लोगों ने 88 प्रतिशत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी 12 प्रतिशत लोगों तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक समस्या है।

महोदय, 1996-97 में, जब दिल्ली की आबादी 1 करोड़ थी, तब हमें 900 एम.जी.डी. पानी मिलता था, लेकिन आज, जबकि 1996-97 से लेकर वर्ष 2019 हो गया है, लगभग 22-23 साल हो गए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बात न करें।

श्री संजय सिंह: दिल्ली को अभी भी 900 एम.जी.डी. पानी मिलता है। दिल्ली को 900 एम.जी.डी. पानी से अपना गुज़ारा करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर कार्य करें।

महोदय, अभी पिछले दिनों दिल्ली के हमारे मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मिले थे, जो जल शक्ति मंत्रालय का पूरा कार्यभार देख रहे हैं। उन्होंने उनसे अनुरोध भी किया था कि दिल्ली में पानी के संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार हमारी मदद करे। दिल्ली में विशेष तौर पर इस जल संकट को दूर करने के लिए हम वर्षा के पानी को संकलित करना चाहते हैं, उसको संचयित करना चाहते हैं। मान्यवर, उस जल संकलन की व्यवस्था के लिए यमुना के आसपास केन्द्र सरकार के सहयोग के बगैर, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी परमिशन, उनकी स्वीकृति के बगैर जल का संचयन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि दिल्ली के अन्दर जल के संकट को खत्म करने के लिए वर्षा के पानी के जल संचयन करने का जो प्रोजेक्ट, जो योजना अरविन्द केजरीवाल जी ने बनाई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए, पीने के पानी के संकट को दूर करने के लिए बनाई है, उसमें आप हमारी मदद करें, हमारा सहयोग करें और हमें स्वीकृति प्रदान करें।

मान्यवर, जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, हम लोगों ने दिल्ली में साढ़े चार साल के अन्दर 239 कॉलोनियों के अन्दर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। द्वारका जैसे क्षेत्र, संगम विहार क्षेत्र, देवली जैसे क्षेत्र, जहां पर पीने के पानी को लेकर लड़ाइयां होती थीं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में, देश की राजधानी में पीने के पानी की समस्या को लेकर हत्या तक की घटना हुई है। जब मैं दिल्ली आया था, तो मैंने पहली बार 'टैंकर माफिया' जैसा शब्द सुना था। इसके पहले अपहरण माफिया होते थे, लूट माफिया होते थे, लेकिन दिल्ली में 'टैंकर माफिया' शब्द मैंने पहली बार सुना था। उस टैंकर माफिया के राज को साढ़े चार साल की अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार ने अपने प्रयासों से, मेहनत से खत्म किया और आज हम हर जगह दिल्ली में पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह अकेले हमारे वश की बात नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर इसमें हमें केन्द्र सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा, अगर दिल्ली के लोगों के प्रति केन्द्र सरकार की एक सकारात्मक दृष्टि नहीं होगी, अगर वर्षा के पानी के जल संचयन के लिए हमें सरकार स्वीकृति नहीं देगी, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और बढ़ेगी और गम्भीर होगी। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं, वह यह है कि 2020 तक दिल्ली में ऐसा भयंकर जल का संकट पैदा होने वाला है, जिससे हाहाकार की स्थिति होगी। उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। एक सहयोगात्मक भावना के तहत हम लोग आगे बढ़ें और हम दिल्ली में उस योजना को लागू कर सकें, जिसमें वर्षा के जल के संचयन और दिल्ली के पानी के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए हमारे प्रयासों में केन्द्र सरकार अपना सहयोग दे।

[श्री संजय सिंह]

मान्यवर, दूसरी बात, अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, तो अभी मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड गया था। बुंदेलखंड में हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, वहां बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए। आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है, तो वह पीने के पानी की समस्या है। वहां पीने के पानी की समस्या इतनी गम्भीर है कि वहां ललितपुर के इलाके में मैं एक ब्लॉक में एक गाँव में गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों ने मुझसे डिमांड की,आजादी के 72 साल के बाद पूरा गाँव एक एप्लिकेशन लेकर मुझसे मिलने के लिए आया और माँग यह कर रहा था कि अपनी सांसद निधि से आप इस गाँव में बोरिंग करवा दीजिए, हैंड पंप लगवा दीजिए।

श्री उपसभापति: मैं पूरे सदन से आग्रह कर रहा हूँ कि आज देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक यह पानी की समस्या है। कृपया हम लोग इस पर गम्भीरता से सोचें और देश को एक संदेश दें कि ऐसी चीजों के बारे में हम किस ढंग से गौर करते हैं और अपर हाउस कैसे गम्भीरता से इस पर डिसकस करता है। संजय जी।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, पूरा गाँव मुझसे मिलने के लिए आया और उन्होंने एक ही अनुरोध किया कि हमारे गाँव में पीने के पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पानी का स्तर बहुत नीचे है, आप अपनी सांसद निधि से एक बोरिंग करा दीजिए। जो लोग मिलने आए थे, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के पाँवों में चप्पल नहीं थी। वे दुश्वारियों में अपनी जिन्दगी जीते थे। उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं थे। उनके पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं थे। हम यहाँ बैठ कर चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें, लेकिन आपको बुंदेलखंड के गाँवों में जाकर परिस्थितियाँ देखनी चाहिए। मैंने अपनी समस्या बताई कि मैं दिल्ली का सांसद हूँ, इसलिए 25 लाख रुपए तक की ही निधि बाहर दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस गाँव में एक हैंड पंप लगवाने का प्रयास करूँगा या ऐसा प्रस्ताव अपनी ओर से दूँगा। यह जल का संकट बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। उन लोगों ने मुझे बताया कि गांव के अंदर जो तालाब बने थे, जिन तालाबों से लोग पीने का पानी लेकर जाते थे, अपने छोटे-मोटे काम कर लेते थे, उन तालाबों की जमीनों पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मंगवाइए। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर तालाबों की जमीन पर भू-माफियाओं ने, गांव में रहने वाले दबंगों ने कब्जा कर लिया है। अगर आपको इस जल संकट से निपटना है, तो उन सारे तालाबों पर हुए कब्जों को आपको हटवाना पड़ेगा। अगर आप इस जल संकट से निपटना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां से और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां से रिपोर्ट मंगवाइए और सच्चाई जानिए। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: सर, इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय मंत्री लोग खड़े होकर आपसी चर्चा कर रहे हैं।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, यह ठीक बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आपने कहा, उसके बाद भी कोई आपकी बात नहीं मान रहा है।

श्री उपसभापति: मैंने उनसे कह दिया है, आप अपनी बात कहते रहें। आपके लगभग दस मिनट पूरे हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी, मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं, कृपया सदन में बात न करें।

श्री संजय सिंह: यहां पर नेता सदन भी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया, थोड़ा ध्यान दें।

श्री उपसभापति: मैं आप सबसे पुन: आग्रह कर रहा हूं, कृपया आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**... आप आपस में बात न करें, कृपया बैठ जाएं।

श्री संजय सिंह: बाकी लोग भी थोड़ा ध्यान दें। इसमें कौन सी बुरी बात है?

श्री उपसभापति: संजय जी, अब आप अपनी बात खत्म करें, क्योंकि अब मैं दूसरे वक्ता को निमंत्रित करने वाला हूं।

श्री संजय सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, देश भर में जितने तालाबों पर कब्जा हुआ है, उनको हटाया जाए। जल संकट के लिए एक बहुम प्रमुख कारण यह भी है। उन तालाबों की जमीनों पर जो कब्जा हुआ है, उस कब्जे को हटाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज नहीं, लगभग 20 साल पहले ही आदेश दिया था कि कम से कम आप देश भर के तालाबों के ऊपर से कब्जे हटवाइए। गांवों में जमीनों पर जो कब्जा कर लिया गया है, उसको दूर कीजिए, तभी पानी की समस्या दूर होगी।

महोदय, आज बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका, उत्तर प्रदेश के साथ सटे हुए मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का इलाका, राजस्थान का इलाका, गुजरात के कई सारे इलाके, कच्छ का इलाका, जिसका जिक्र अभी प्रधान मंत्री जी भी कर रहे थे, इन सभी इलाकों में जल का भारी संकट है। आज पानी की इस समस्या से दिल्ली भी जूझ रहा है, तमिलनाडु भी जूझ रहा है, बंगाल भी जूझ रहा है और उड़ीसा भी जूझ रहा है। पूरा देश आज जल संकट की इस गंभीर समस्या से जूझ रहा है। आपके माध्येम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस संकट में राज्यों के साथ सहयोग करने के लिए आगे बढ़ें और इस संकट को दूर करें, धन्यवाद।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, जल संकट के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी उल्लेख किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि अब जल शक्ति मंत्रालय को विशेष महत्व देते हुए, अलग से ही मंत्रालय स्थापित करने का काम हो गया है। वैसे भी सृष्टि की रचना में पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व माने गए हैं। यह जो शरीर बना है, उसमें भी जल-तत्व की बहुलता है। जल के बिना सब सूना है और जल की आवश्यकताओं को हम सब समझते हैं। कहा भी गया है,

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।

यह जो पानी है, यह एक तरह से मनुष्य की पहचान का पर्याय हो गया है। सृष्टि में भी जो पानी है, उसकी ही बहुलता है, पृथ्वी का हिस्सा तो बहुत कम ही है। जब हम पानी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत में वर्षा से प्राप्त पानी कुल जल उपलब्धता प्राय: 4,000 बिलियन घनमीटर है। जहां पानी होता है, वहां उसका वाष्पीकरण भी होता ही है। जो बचा हुआ जल है, वह 1,870 बिलियन घनमीटर है। परन्तु उपयोग के लायक जो पानी हमारे पास बच जाता है, वह 1,137 BCM है, जिसमें 690 BCM सतह पर दिखाई देता है और जो भूजल है, वह 447 BCM है। यह जो पानी है, जितना है, उतना है। अब इसको किफायत से उपयोग करने की आदत होनी चाहिए। देश की जनसंख्या का दबाव और प्रभाव निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, माँग बढ़ती चली जा रही है। उस आधार पर 2010 में यह जो हमारी माँग थी, वह 710 BCM थी, यह 2025 में बढ़ कर 843 BCM आंकी गयी है। इसके अतिरिक्त देश में 2050 में पानी की जो कुल माँग हो जाएगी, वह 1180 BCM आंकी गयी

[डा. सत्यनारायण जटिया]

है। परन्तु जब 2050 होगा और हमारे यहाँ उपलब्धता केवल 1137 BCM की होगी, तो निश्चित रूप से पानी के बारे में जो कमी आयेगी, उसकी पूर्ति करने के उपाय हमारे पास नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जल संचयन को प्राथमिकता देते हुए, उसके संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना ही चाहिए। ग्रीष्म काल के मौसम में यह जो कठिनाई है, यह तो और ज्यादा बढ़ जाती है। अनेक प्रदेश इस संकट से जूझ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन सारी बातों को करने के लिए जो उपाय हमारे पास हैं, वे सीमित ही हैं। जिन-जिन प्रदेशों में जल संकट है, उसको देखते हुए उसके निराकरण के उपाय-- क्योंकि यह जो जल है, यह राज्य का विषय है, ऐसा माना गया है। इसलिए जल को जो राज्य का विषय माना गया है, उसका संचयन करने का काम, सुरक्षित रखने का काम और उसको प्रदूषणमुक्त करने के काम करने का दायित्व भी उसी पर आता है। किन्तु चूँकि जल बड़ा महत्वपूर्ण भी है उसके लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के आयोग भी बिठाये गये हैं, 2012 में जल आयोग बनाया गया था। उसने कुछ सिफारिशें की हैं। इस प्रकार इन सारी बातों का तो सिलसिला चला हुआ है। हम लम्बे समय से नदियों को जोड़ने की बात भी करते रहे हैं। अच्छी बात है। नदियाँ जुड़नी चाहिए, जैसे सड़कों को जोड़ कर हमने राष्ट्रीय सम्पर्क को बहुत अच्छा बनाने का काम किया है।

पीने के पानी का या जल का जो उपयोग है, वह तो विविध प्रकार का है। सबसे पहली प्राथमिकता पीने के पानी की आती है। पीने के पानी के बाद इसका उपयोग कृषि के लिए होता है और उसके बाद औद्योगिक जल के रूप में भी होता है। इस प्रकार से हम पानी का उपयोग करते आते हैं। किन्तु पानी की शुद्धता को बनाये रखने के लिए जो उपाय होना चाहिए, उसमें जो प्रामाणिकता चाहिए, वह प्रामाणिकता करने के प्रबंध हमें और चाक-चौबंद करने होंगे। नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, प्रदूषण मुक्ति के उपाय हमने किये हुए हैं, किन्तु हम नदियों में पानी का हाल देख रहे हैं कि कैसा हो गया है। पहले तो नदियां पवित्रता का पर्याय ही हैं। यदि हमने गंगा कह दिया, तो इसका अर्थ यह है कि गंगा है, यानी पवित्र है। नदियों को हम मां के अनुरूप में भी देखते हैं। इसलिए यह जो पवित्रता है, वह उसकी शुद्धता पर ही निर्भर करती है। उस शुद्धता को बनाये रखने के लिए जिम्मेदारी यदि कहीं आती है, तो हम पर ही आती है। हमने इन सारी बातों को करने के लिए जो उपाय किये हैं, वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, हां, कोशिश जारी है। जिस प्रकार से नगरों से पानी निकलता है, वह पानी सीधा नदियों में नहीं जाए। उसकी रोकथाम करके, उस पानी को डायवर्ट करके उसका उपयोग वहीं कर लिया जाए और नदियों में वह पानी नहीं जाए, तो यह शुद्धता बनी रह सकती है। ...**(व्यवधान)**...

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): महोदय, जिन माननीय सदस्य ने शुरू किया था, वे खुद ही गायब हैं। ...**(व्यवधान)**... यह बहुत गम्भीर विषय है। वे स्वयं उपस्थित नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

डा. सत्यनारायण जटिया: कोई बात नहीं। ...**(व्यवधान)**... कोई बात नहीं। जो गये हैं, उनको जाने दो और जो उपस्थित हैं, उनको समझने दो, समझाने दो।

यह विषय तो गम्भीर है ही। जब हम सब गम्भीर हैं और पानी के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रू से यह कोई एक व्यक्ति का विषय नहीं है, यह तो पूरे राष्ट्र का विषय है। उस दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष पानी की जो कमी आयी है, यह पिछले कई वर्षों के बाद, 65 वर्षों के बाद आयी है। एक बार पहले 2012 में भी कोई ऐसा मौका रहा होगा, परन्तु इसवक्त जो पानी की कमी आयी है, मानसून का जो विलम्ब हो गया है, उसके कारण से भी हमारी यह

कठिनाई बढ़ती चली जा रही है। पानी की कमी का असर जन जीवन पर तो पड़ ही रहा है और मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी राजस्थान से आते हैं। वहां बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे इलाकों में मीलों तक पानी नहीं है। पानी की आस में लोग दूर-दूर तक चले जाते हैं।

"कोई तो पेड़ घना होगा,
प्यासी-प्यासी धरती का कोई तो मेघ घना होगा।"

पानी की तलाश में, आशा में लोग मीलों चलते चले जाते हैं। इस मृगतृष्णा के कारण जो परेशानी होती है, पीने के पानी की तलाश में पूरा-पूरा दिन लग जाता है। महिलाओं को इसमें सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं लेकिन महिलाओं की परेशानी को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार इस संबंध में योजना बनाकर पानी की कमी को दूर कर सकती है। इसके लिए ठोस उपाय करने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों पर, जैसा यहां कहा गया है, सावधानीपूर्वक कदम उठाने चाहिए। केन्द्रीय जल आयोग, जो देश के 91 प्रमुख जलाशयों की निगरानी करता है, उसने भी वर्तमान पानी के स्तर को पिछले 10 सालों के स्तर से 20 प्रतिशत कम पाया है। 20 प्रतिशत कम पानी होने के कारण पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जलाशयों का जलस्तर भी कम हो गया है, भूमिगत जलस्तर भी कम हो गया है। जो हमारे कुएं, बावड़ी और दूसरे जल स्रोत थे, पोखर थे, वे सब सूख गए हैं।

श्री उपसभापति: जटिया जी, अब समाप्त करें क्योंकि आपके दल से और 4 लोगों को बोलना है। आपके पास कुल 40 मिनट का समय है, सबको मिलाकर। अब आप बोलें।

श्री सत्यनारायण जटिया: राज़ी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा है। पानी हो तो वाह-वाह है, अगर पानी नहीं तो परवाह है। जलाशयों के सूख जाने के कारण जो समस्या उत्पन्न हो गई है, इसकी चेतावनी मिलने के बावजूद हमने जो उपाय करने थे - कुछ तो manual उपाय हो सकते हैं, कुछ ऊपरी तौर पर हम उपाय कर सकते हैं। शहरों में ऐसे उपाय हम करते ही हैं, जहां पानी जल टैंकरों से पहुंचाया जाता है, परन्तु जो दुर्गम स्थान हैं, जहां पानी पहुंचाने के लिए हमारे पास साधन नहीं हैं, ऐसे स्थानों पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसकी है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वर्षा का जल संचयन करने के निर्देश दिए गए हैं, Water harvesting के लिए शहरों में कहा गया है किन्तु उनका पालन कराने के साथ-साथ नए-नए बांधों का निर्माण कराने की भी आवश्यकता है। मैंने स्वयं MPLADS से अपने क्षेत्र में 5 नदियों पर 25 से ज्यादा बांध बनाने का काम किया है। इसलिए पानी की उपयोगिता के बारे में मेरे मन में हमेशा यही विचार रहता है। हमारे देश में 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया गया था। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश में जय जवान के साथ-साथ जय किसान भी होगा। हमारा जवान तो सीमाओं पर रहता है जबकि किसान मैदान में, खेतों में काम करता है। यदि किसान की जय करनी है तो उसके हित में हरित क्रांति लाने के उपाय करने की, जल का प्रबंध करने की जरूरत है। इसीलिए मेरी पानी को लेकर प्राथमिकता रही है। ऐसी स्थिति में rain water harvesting...

श्री उपसभापति: जटिया जी, आपके 10 मिनट पूरे हो रहे हैं।

श्री सत्यनारायण जटिया: मैं आधे मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूं। जो हमारा जल संचयन का कार्यक्रम है, जैसा मैंने कहा कि इसके लिए MPLADS के माध्यम से भी काम किया जा सकता है, इसके माध्यम से भी जल-संचयन के कामों को करना चाहिए। कोई पानी से महरूम रह जाए, यह ठीक नहीं है। पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दृष्टि से सरकार ने जो जल मंत्रालय बनाया है, निश्चित रूप से,

[डा. सत्यनारायण जटिया]

विशेष रूप से इस पर ध्यान देगा। अभी तक जितनी रिपोर्टें आई हैं, उन्हें कार्यान्वित करने और बड़ी योजनाएं बनाने की दृष्टि से भी काम होना चाहिए। उत्तर में जो नदियां बहती हैं, उनमें पानी काफी है, पूर्व में बहने वाली नदियों में भी काफी पानी है, जबकि दक्षिण में पानी की कमी है, कर्णाटक और तमिलनाडु में पानी की कमी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए उपाय करने चाहिए। इन राज्यों को विशेष सहायता देकर, जब यह मानसून विलम्ब से पहुंच रहा है, उसके लिए सरकार जरूर प्रबंध करे और ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपसभापति: आपका भी धन्यवाद। डा. अमी यज्ञिक।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on a very important subject of water scarcity. We talk about development, but we forget the human angle of development. The NITI Aayog has just released a Report in 2018 and has stated that almost 21 cities of this country will face absolutely zero ground water level by 2020. Sir, this poses a very grave concern. The Ministry of Jal Shakti which has just come into existence has to deal with these issues. Sir, the causes are known to everybody. Many hon. Members have mentioned about the causes of water scarcity. We have faced drought conditions. We have also had weak monsoons. But the problem seems to be that we are unable to use the water which we already have. Sir, for example, Gujarat is a very developed State, but if you walk into the interiors of the districts of Gujarat, you will find the same lines which one of the speakers, Mr. Sanjay Singh, have mentioned just now. Sir, you will see women standing in queues with plastic containers to get water. They get water by tankers. Sir, even in urban areas of some cities in Gujarat, there are water tankers which are given on alternate days. I have been a party to a petition also in the Gujarat High Court, where we had requested the court that there should be a water tanker supply on alternate days in some specific areas. Sir, the issue of water scarcity is not new to us. It is not something which has suddenly come up. The problem is that we do not have the infrastructure that is required for the collection of water. The Government is saying that by the year 2024, every household will have a water pipe or a water connection. Sir, the question is not, or the query is not, or the doubt is not, that the Ministry will not be able to do it or the Government will not be able to do it. But the question is how will they do it? From where will the drinking water come? Sir, we have not been able to give a plan for reuse of the sewage water. We have not been able to give a plan to reuse the polluted water. We do not have a plan in place for sewage treatment of the water and that is why this polluted water cannot be made use of. We do have dams. Sir, 276 dams in Gujarat have not been recharged at all. And ground water recharge is one of the methods to give water to the people. We cannot just go talking like, yes, we are for the poor people and we are for the disadvantaged class, without giving them any service. We

want children to study, but there is no water in the toilets in the schools. So, what is the plan? Are we going to use the ground recharge method? Are we going to have an irrigation project for small towns? Are we going to recharge the dams? Are we going to do rain water harvesting? Sir, I can speak endlessly on this subject because water scarcity is going to be the issue of the century; not locally, not nationally, but globally. How are we going to deal with it? Sir, if we want to become the economy that we want to become in future, then we have to see that the water reaches the last person. What is the plan in place for that? What is NITI Aayog going to do about it? It comes out with a report that 21 cities are not going to have any water by the year 2020, then what is the plan in place? If we say that the reports in the past were not dusted and are not drop out, what are you going to do now? What is the assurance that you are going to give to the people? Are these reports going to be implemented? That is the question. Sir, the causes are numerous. Today, the issue is to think about the ways to treat these causes. Sir, we cannot tell the citizens that you should start rain water harvesting individually. We need to have a proper plan, a proper infrastructure or a proper methodology, to spread awareness, to give them the facility so that they can do rain water harvesting. That is one aspect.

Sir, while talking about water scarcity, we may also keep in mind about drinking water, *i.e.,* potable water. We should also talk about non-potable water which is being spoiled every day. It goes as waste. Sir, there is no method to treat that water. We should see that how this can be segregated. There is a survey that about 25 liters of water is required by one human being every day for his hygiene, drinking, cooking and all those things, but the rest of the water is not used for that purpose. How do you segregate these two kinds of waters? How do you make a plan at the Municipal level or at the State level or at the National level? Yes, clubbing the rivers together, bringing the canals together is a solution, but it is a larger programme. I am talking about a programme that will reach the common person, that will reach the person who is residing in villages. What are you going to do with the lakes? The lakes have been encroached. We find industries on the lakes. We find that the landlocked bodies are completely without water. So, Sir, I would say that this topicis very important. It is not important in the sense that it is a topic but it is important because it is touching everyone' s everyday life. So, it should be given topmost priority. Where is the water going which is already there? Is it being diverted to the industry; is it going to the farmers or is it going to the citizens for drinking water? So, the question is, what are we going to do about it? This debate needs a larger discussion, very, very proactive steps from the Government as well as participation by the people of this country along with the Government in order to solve this issue because water is the lifeline of every human being. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for making brief and nice points.

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): Sir, I just want a clarification from the hon. Member. She used the words, ' recharging of dams'. I just wish to understand her intent and ask what does she mean by ' recharging of dams' ?

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I don't want to use harsh words but we have small dams, and, most of the times, people living in those small areas, whether they are districts or villages, they have bori-bandh dams. They prepare small dams on their own because they do not wait for the funds from the Government or they do not wait for the Government to step in. That is where the complementary part of the NGOs comes in. They come in to lend a helping hand. They get all this technology, they learn about this technology internationally, and, they bring it down to the village level. When there is rainwater or rain, the surface water, which percolates to the ground level, is completely pumped out by the industry, and, then, reverse pumping is done by polluting the ground water level. That surface water which goes down to the ground level is being taken as water and it is recharging those small dams. We are not talking about big dams like Narmada. This is recharging of dams and that is one of the basic fundamentals of recharging of small dams.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri R. Vaithilingam.

SHRI R. VAITHILINGAM (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, *Vanakkam.* I thank you for giving me this opportunity to speak on this important issue. I am indeed thankful to this august House for taking up the discussion on the challenges of water crisis including the supply of drinking water in the country. Water issues are of permanent nature. Saint Thiruvalluvar said, "If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen" . There is a blame game going around which I do not support. We should see this water crisis as an issue concerning the present and the future of this country. There should be a national plan and policy for water related issues.

Sir, on one side, Tamil Nadu faces severe drought, and, on the other, it faces floods. The annual per capita income of water in Tamil Nadu is 860 cubic meters as against the national average of 1,869 cubic meters. Tamil Nadu has tapped almost all of its surface water resources and has to look sources beyond its frontiers to meet the needs of its growing population.

Despite the severe drinking water crisis in the country, I should make a mention that the Tamil Nadu Government has taken several measures to address this issue. We have to follow the bucket culture instead of shower culture. Water should be used meticulously. Chennai used to be one of the water-surplus metropolitan cities in the country till a couple of decade ago. Following the age-old water conservation tradition of Tamil Nadu, Chennai had nearly two dozen water bodies including three rivers and a British period Buckingham

Canal. Population explosion and several other factors have added to water woes. I would like to stress that a coordinated approach of the Union Government and the State Governments along with the support of people can only get this issue addressed. Water issues can be addressed in several ways.

On interlinking of all the rivers, especially the rivers flowing through the southern part of the country, the only solution to provide water to water-starved Tamil Nadu is to transfer water from the Godavari, which is a surplus basin, to the Cauvery.

The Central Water Commission has estimated that the Godavari basin has an annual surplus of about 300 TMC of water which can be diverted to other peninsular rivers. I request you to link the Godavari river in Andhra Pradesh with the Cauvery river on a priority basis.

We should encourage the Governments at the State level, local bodies and the people to follow traditional ways of water conservation. Kudimaramathu is an age-old practice wherein public participation is encouraged in a big way for restoration of water bodies. As many as 1,600 water bodies have been desilted in the State at a cost of ₹500 crore. The Union Government has to create a separate fund and help the States.

I now come to national action plan for drought mitigation measures. Tamil Nadu faced a severe drought in the year 2017 and the State Government provided ₹ 2,247 crore as relief to the farmers. Again, all the districts of Tamil Nadu are now facing severe drought with Chennai and neighbouring districts facing severe water shortage. The Tamil Nadu Government has taken a number of drought mitigation measures. We need more assistance from the Union Government for 400 MLD sea water reverse osmosis desalination plants at Perur at a cost of ₹ 6,078 crore, and the Union Government should provide gap funding to the tune of ₹ 1,810 crore over and above JICA loan, and also for tertiary treatment of waste water for industrial use at a cost of ₹ 1,900 crore.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only two more minutes.

SHRI R. VAITHILINGAM: Another major initiative is construction of 383 check dams and water conservation structures at a cost of ₹ 736 crore. However, these efforts require special allocation of ₹ 1,000 crore annually for States like Tamil Nadu where drouqht is so frequent.

Rain water harvesting is the brainchild of our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma. We have made rain water harvesting structures mandatory far all constructions in Tamil Nadu. I request that rain water harvesting should be made a pan-India movement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have only one more minute and then I will move to another speaker.

SHRI R. VAITHILINGAM: Rejuvenation of the Cauvery river, the sacred river of the south, should be done on the line of Namami Gange Scheme. I request the Union Government to support the Scheme of Rejuvenation of the Cauvery which will cost approximately ₹ 7,000 crore to ₹ 10,000 crore. I request the hon. Minister of Environment, Forest and Climate Change to advise Kerala not to deny the required clearances to enable the Government of India, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to accord the clearances to the Government of Tamil Nadu to carry out the remaining works as per the judgment of the Supreme Court and to restore the water level in the Mullai Periyar Dam to FRL of 152 feet.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude; otherwise, I will move to the other speaker.

SHRI R. VAITHILINGAM: Due to the untiring efforts of our revered leader, Puratchi Thalaivi Amma, and due to the intervention of the hon. Supreme Court, the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal dated 5.2.2007 was published in the Gazette of India on 19.2.2013. As per the orders of the hon. Supreme Court dated 18.5.2018, the Government of India notified the Cauvery Management Scheme, 2018 in the Gazette of India on 1.6.2018 to give effect to the decision of the Tribunal as modified by the hon. Supreme Court. *(Time-bell rings)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Your one more minute is over. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Manas Ranjan Bhunia. ...*(Interruptions)*... Only your speech will go on record . ...*(Interruptions)*...

SHRI R. VAITHILINGAM: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaithilingam, please ...*(Interruptions)*...One minute is already over ...*(Interruptions)*... I am not allowing you . ...*(Interruptions)*... Now, Shri Manas Ranjan Bhunia. Only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA (West Bengal) : Sir, how can I speak? ...*(Interruptions)*... Make him sit down. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... I have already given more than this .... (Interruptions) ... Shri Manas Ranjan Bhunia, you please speak . ...*(Interruptions)*...

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, how can I? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, I would call the next speaker. ...*(Interruptions)*... Please, please ...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded

4.00 P.M.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, please reset the time . ...*(Interruptions)*... What is going on? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, please give him two more minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has already taken more than two minutes. ...*(Interruptions)*... There is time constraint. ...*(Interruptions)*... Manas Ranjan Bhuniaji, you please speak.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, how can I? ...*(Interruptions)*... Please bring the House in order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair will not give time under pressure. ...*(Interruptions)*... Already, I have given him two more minutes. ...*(Interruptions)*... Shri Manas Ranjan Bhunia, you please speak. ...*(Interruptions)*... This is not fair. ...*(Interruptions)*... Navaneethakrishnanji, please ask him to sit down . ...*(Interruptions)*...

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, what a horrible situation is going on! ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your Member to sit down. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, what is this going on? ...*(Interruptions)*... Sir, please reset my time. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not good. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Manas Ranjan Bhunia.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Thank you very much, Sir. Today in this august House, an issue has come up for discussion which is the need of the hour. Hon. Minister, Mr. Shekhawat, took a meeting and held a press conference on 11th of June in Viqyan Bhawan where he mentioned about the analysis of NITI Aayog report and Composite Water Management Index, which came out in the month of June, 2018. After the analysis of the Niti Aayog Report, Composite Water Management Index came out in the month of June, 2018. There, he observed ... I have read in the media - - that a mission would be fixed within 2024 to make India free from water crisis. It is very nice to see the Government' s planning. He said -- the observation of Niti Aayog after starting water investigation with Drinking Water Department and Rural Development Department -- that only 18 per cent of the households of India out of 19,19,00,000 households throughout India spread over all

[Shri Manas Ranjan Bhunia]

the States have pipeline water at this moment. That means 82 per cent of the households do not have safe and pure pipeline drinking water at this moment in India.

He also made a very serious observation. Per capita necessity of water supply has been reduced drastically. He cited one example. In the year 1950, the per capita supply was 5,000 cubic metres but in 2019, it has come down to 1,400 cubic metres, at this moment, in India. It is such a serious situation. So, we stand throughout India in this deep crisis of water. The life is water and the water is life. So, we are pressed between the two situations which has threatened the existence of human society, the human life including animals also and as a whole earth.

Sir, this is a very interesting point. The Niti Aayog came out with the observation. What is the observation? The observation is that 60 crore people, 600 million people, are suffering from acute crisis of drinking water out of 120 crores of population of India. Sir, 75 per cent of India' s households do not have water supply in their premises and 84 per cent of rural households do not have pipe water access. It is very unfortunate to quote that India ranks 120 in Water Index out of 122 countries. We, the people of India, are facing such a horrible situation at this moment.

Sir, we are grateful that you allowed this discussion to bring to the notice of this Government that there is something for which it ought to take serious step and take action immediately to ameliorate this situation in our country for water crisis. The most interesting chapter is India with its historical existence, we used to read in the history that kings and nawabs and the rulers used to go for digging big ponds and jheels to conserve water during rainy season, and connectivity of the rivers to get more access to water was planned during that period.

Sir, I am very happy to inform this august House that our Government in West Bengal under the leadership of Madam Mamata Banerjee has taken up a beautiful project - ' Jal Dharo, Jal Bharo' . In this context, we have, at this moment, 31,31,000 ponds already dug and excavated to preserve the rain water and to have more water in our different districts which have been facing the water crisis, particularly, Bankura, Purulia, Midnapore, Birbhum, Burdwan and other districts including the saline zone nearing coastal area. So, we are getti ng a beautiful result. Sir, now, at this moment, with the expenditure of ₹ 1,451 crores and ₹ 1,742 crores, we are going to meet the need of 60 per cent of the entire population of Bengal with pipeline water and purest water. After the completion of all the projects within a few months, we will be able to meet the demand and to confront the crisis to the tune of 75 per cent of the people of Bengal.

So, Sir, my urge and my appeal to the Central Government, through you, is that the time has gone and it is too late but we have to start immediately. We can study the vision of the Government academically but the reality is this that we are facing a reeling condition of the water crisis in India. The most interesting thing is, I have gone through a report published in The Times of India regarding a boy of Marathwada region, a ten year old boy, उसका नाम सिद्धार्थ धागे है। He has to travel 14 kilometres by train from Mukundwadi Railway Station to Aurangabad to get two cans of water every day. It is such a pitiable situation. It is not a question of Maharashtra, Maratha, Kerala, West Bengal nothing, but this is a situation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Bhuniaji. Please conclude.

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: So, my appeal to the Government, through you, is we should not waste a single minute by thinking, by preparing the papers, to prepare a project report to consider it by the Finance Department, NITI Aayog all these things. Let us start immediately from tomorrow what is to be done. I shall request the hone Minister, Shri Shekhawat to please come out with your statement as to what is the agenda of the Government to address this serious problem of water crisis that the people of India are facing nowadays.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि संसद ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संज्ञान लिया है। Schedule के हिसाब से मानसून लेट हो रहा है। यह खेती करने वालों का देश है इसलिए इससे एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लग गयी है। पूरे देश में जो खबरें आ रही हैं, जितना पानी अब तक गिरना चाहिए था, वह विलम्बित हुआ है। अभी हमारे साथी भाई विशम्भर प्रसाद जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में जो पानी के टैंकर जाते हैं, उनमें लूट होने लग गयी है। पाठा, बांधा, महुआ और ललितपुर में पानी 600 फुट से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। यह केवल बुंदेलखंड की कहानी नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत की कहानी है। मैं अभी डेटा देख रहा था। नासा ने जो ground water का डेटा दिया है, 2018 में जो जनवरी में पानी की उपलब्धता थी, दिसम्बर, तक वह उससे आधी रह गयी थी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. This is the most important issue that we are discussing.

श्री रवि प्रकाश वर्मा: यानी जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वह हमारा जीवन है, चाहे हमारी खेती है, चाहे हमारी औद्योगिकी प्रक्रियाएं हैं, सबमें पानी का रोल होता है। उन्हें एक बड़ा झटका लगने की संभावना सामने आ रही है। हमारे माननीय मंत्री जी - जिन्हें अभी नया मंत्रालय मिला है, बहुत जिम्मेदारी का मंत्रालय है - उन्हें यह देखना पड़ेगा कि जब हिन्दुस्तान को हम लोग fast development grown के pace पर ले जा रहे हैं तो development growth का एक water footprint भी होता है। जितना पानी आपके पास available है, आप उतना ही development का process achieve कर सकते हैं। अगर पानी उपलब्ध नहीं होगा तो आप कोशिश करते रह जाएंगे, कभी लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। सर, कई विद्वानों ने भी जिक्र किया और माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि धरती पर पानी को लेकर जो conflict बन रहा है, अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

वह पानी के लिए होगा। इस बात से यह पता लगता है कि यह विषय कितना गंभीर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक प्यास गले तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक पानी मिलता बंद नहीं हो जाता है, तब तक पानी को लेकर कोई सीरियस होना पसंद नहीं करता है।

सर, आज जलवायु परिवर्तन सामने आ रहा है। हमारा जो behaviour है, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, बड़े पैमाने पर इन्होंने वायुमंडल को बदला है और वायुमंडल के बदलने से, जो वर्षा का स्तर है, वह भी बदला है अभी जटिया जी बता रहे थे कि भारतवर्ष में जितना पानी बरसात में गिरता है, उसका केवल एक-चौथाई पानी ही हम जमीन में percolate कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी सब बह जाता है। आज जब पानी के बारे में बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को, हमारी भारत सरकार को भी पानी को एक priority agenda के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। चूंकि आपके पास एक separate Ministry है, अभी जितने भी मंत्रालय हैं, पूरे देश में हमारी जितनी भी हमारी activities चल रही हैं, उनका जो water footprint है, उनकी जो पानी का आवश्यकताएं हैं, उसको देखते हुए एक National Blueprint बनाए जाने की जरूरत है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कई प्रयास किए हैं, तालाब भी खोदे गए हैं, कुएं भी खोदे गए हैं, कोर्ट ने भी फैसले किए थे और उत्तर प्रदेश में हमारी जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर तालाब खुदवाने का काम किया था, recharging ponds बनवाने का काम किया था। लगभग सारी सरकारें ये काम कर रही हैं, औ यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, चाहे वे नगरपालिकाएं हैं, चाहे वे हमारी ग्रामीण पंचायतें हैं और चाहे जिला पंचायतें हैं, इनकी जो functioning है, जिस तरीके से वे development agenda set करते हैं, सर, मुझे अफसोस है कि कहीं पर भी आज तक एक ऐसी mandatory situation नहीं बनाई गई कि कितना पानी उपलब्ध होना चाहिए, उस पानी की व्यवस्था कैसे होगी? साथ ही उसके लिए experts के माध्यम से district-specific blueprint बने कि कैसे पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी, कहां-कहां पर कुएं बनाए जाने की जरूरत है, कहां-कहां recharging की जरूरत है और उसके अंदर कहां-कहां hurdles हैं, क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, कौन-कौन सी बड़ी industries हैं, जो बड़ी प्रभावशाली industries हैं, जो बहुत ज्यादा पानी निकाल कर ले जा रही हैं? सर, जमीन के नीचे पानी बनता नहीं है, वहां रखा हुआ है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसको लेकर एक judicious policy को हमारी जिला पंचायतों को, जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो हमारी नगरपालिकाएं भी हैं, उनको तय करना पड़ेगा और experts की मदद से तय करना पड़ेगा। भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वह कोई ऐसा system खड़ा करे कि नगरपालिकाओं में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जहां कहीं groundwater की खपत हो रही है, उसके विषय में बड़े पैमाने में experts और एक digital data available रखें। जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जिनको हम सिखा रहे हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में नई उम्र के बच्चों ने climate change को national agenda बना दिया है। हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारे बच्चे भी सामने आएं और वे climate change को एक national agenda बनाकर आगे बढ़ें। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, वे इसको priority agenda लेकर आगे बढ़ें। सर, उनको बहुत सारा डेटा देने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाने की जरूरत है कि गांव में भी और शहर में भी हर आदमी को यह डेटा उपलब्ध रहे, जिससे पता चले कि हमारे यहां कितना पानी गिरता है, कितना बह जाता है, कितना हम consume कर पाते हैं और उसके लिए कौन-कौन से system बनाए जाने की आवश्यकता है। सर, नगरों में लगभग हर

घर में एक छोटा सा बोरिंग पम्प लगा हुआ है, जो पानी खींचता है। आज तक कभी ऑडिट नहीं किया गया है कि अगर पांच सौ लीटर पानी रोज़ निकाल रहे हैं, तो एक साल में कितना पानी निकालेंगे और यह पानी कहां से आएगा? पॉलिसी बनाई गई थी कि हर घर के ऊपर water recharging system बनाया जाएगा, लेकिन experts नहीं है। वे recharging pits कैसे बनाए जाने हैं? नगरपालिकाओं की प्राथमिकताएं नहीं हैं और पंचायती राज की प्राथमिकताएं नहीं हैं। अभी जटिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जितना पानी हिन्दुस्तान में बरसता है, कुदरत हमें देती है, उसे हमें पूरे तौर से utilize करने की जरूरत है और recharging system एक बहुत ही progressive तरीके से, पहले से plan करके, जानकारी करके कि इस साल हमारे इलाके में कितना पानी बरसने वाला है, उसे हम कैसे maximum recharge कर पाएं? अभी संजय सिंह जी बता रहे थे।

श्री उपसभापति: रवि प्रकाश जी, आपके दल से एक वक्ता और हैं। आप 6 मिनट बोल चुके हैं, अब conclude करें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं conclude कर देता हूं। सर, एन.जी.टी. ने भी लगातार वॉर्निंग दी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकारें एन.जी.टी. के जो आदेश हैं, उनको लागू नहीं कर रही हैं। भारत सरकार को कोई ऐसा मेकेनिज्म बनाना होगा, जिससे कि एन.जी.टी. के आदेश हैं, वे पूरी तरह से लागू हो जाएं।

उपसभापति महोदय, जो इंडस्ट्रीज़ पानी इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जो गंदा पानी बहुत बरबाद कर रही हैं। गवर्नमेंट ने zero effluent की पॉलिसी बनाई थी, आज तक हम उसको हंड्रेड परसेंट फॉलो नहीं कर पाए हैं। यह प्राइयॉरिटी सेक्टर है। सर, इस सेक्टर को आप देखिएगा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ पानी डिस्चार्ज कर रही हैं, यह पीने का पानी है, यह दैनिक यूज़ में आने वाला पानी है, इसका जो जीरो डिस्चार्ज है, उसे कवर करें।

सर, हम यह बताना चाहते हैं कि जमीन के अंदर जो पानी है, उससे किसान की आमदनी का सीधा रिश्ता है और यह अन्ना हजारे जी ने रालेगॉव सिद्धि में साबित करके दिखाया है। वहां पर जमीन में पानी नहीं गया था, जब रीचार्ज सिस्टम बनाए गए, तब वहां पर खेती होनी शुरू हुई है। ऐसा करने से वहां लोगों की आमदनी बढ़ी है।

श्री उपसभापति: आपके दल के लिए जो समय निर्धारित है, उसमें अब सिर्फ एक मिनट बचा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं अब कन्क्लूड कर रहा हूं। सर, मैंने जिक्र किया कि एक ऑडिट सिस्टम की जरूरत है। हम लोग जो भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम कैसे ऑडिट करें। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है और उसे मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। भारत सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम बनाया है, लाखों-करोड़ों की तादाद में टायलेट्स बनाए जा रहे हैं। सर, उसमें septic tank के बजाय soakpit बनाया जा रहा है और यह अवैध है। आप जमीन के अंदर जो पानी है, उसे खराब नहीं कर सकते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: रवि प्रकाश वर्मा जी, आपके बोलने का समय खत्म हुआ। आपके बोलने का समय खत्म हुआ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, आपको पॉलिसी चेंज करवानी पड़ेगी। ...(**समय की घंटी**)... जो गांव में शौचालय बन रहे हैं, सर, मेरे यहां पर गांवों से शिकायतें आई हैं कि गांव का पानी नमकीन हो गया। लोग गंदे पानी की बीमारियों से मरने लगे हैं। सर, इस चीज़ को आपको प्राइयॉरिटी देनी होगी।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, रवि जी। ...(**समय की घंटी**)... आपने अपने दल का पूरा समय इस्तेमाल कर लिया है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपसभापति: आप सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, मैं खत्म कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, what is important?

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, सबसे इम्पॉर्टेंट पानी है। अभी इस बात का जिक्र आया था कि शहरों से बहुत बड़ी तादाद में गंदा पानी नालों के माध्यम से नदियों में जा रहा है। सर, मैंने सिंगापुर में देखा कि जितना भी सीवेज वाटर है, उसको रिसाइकल करते हैं। दिल्ली, एन.सी.आर. में पांच करोड़ आदमी रहते हैं और इतनी ही वॉटर बोटल्स पीने के पानी की यहां पर बिकती हैं। हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन हमने गंदे पानी की रिसाइकलिंग पर फोकस नहीं किया है।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्रीमती कहकशां परवीन। अब आपके बोलने का समय खत्म हो गया है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, एक प्वाइंट और है। पानी को रिचार्ज करने के लिए जमीन के अंदर एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाए जाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे लीड लेकर सामने आएं और मुझे लगता है कि इससे हमारे लक्ष्य पूरे हो सकेंगे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्रीमती कहकशां परवीन।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज इस जल संकट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अपनी पार्टी का और अपने नेता का शुक्रिया अदा करती हूं। जल संकट एक ऐसा संकट है, जो हर तबके के साथ और हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है; चाहे वह किसान तबका हो या फिर घरेलू काम-धंधे की बात हो या फिर कि पीने के पानी की बात हो या फिर आम लोगों के जीवन की बात हो या फिर इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों की बात हो।

[उपसभापति (डा. सत्यनारायण जटिया) *पीठासीन हुए]*

मैं सबसे पहले सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आज आपने इस विषय पर चर्चा कराई। कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से हम जल संकट से जूझ रहे हैं। हमारा देश दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जहां पर चार ऋतुएं हैं। हमारे यहां वर्षा ऋतु का बहुत महत्व है। महोदय, सावन का महीना हो या भादों का, वह किसानों, औरतों और आम जन-जीवन के लिए बहुत ही खुशी लाता है। पहले जब औरतें खेतों में रोपाई किया करती थीं, तो उन्हें मालूम होता था कि अगर हम फलां गाना गाएंगे, तो बारिश होगी और उनके द्वारा गाना गाने के बाद, वाकई बारिश होती भी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से वैसा माहौल नहीं है।

महोदय, NASA और दुनिया भर के विद्वानों ने भी कहा है कि विश्व में अब यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो पानी के लिए होगा। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 60 करोड़ भारतीय गम्भीर जल संकट से जूझ रहे हैं और हर साल 2 लाख लोग पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलने के कारण बहुत गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जैसा यहां कहा गया कि देश में कई जगहों पर पोखरों को भर-भर कर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, यह बात सही है। मगर हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा कि आज जो बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनमें या बड़े-बड़े घरों में हम साफ पानी पीने के लिए जो RO वगैरह लगाते हैं, उनसे हमें अगर एक लीटर पानी मिलता है, तो लगभग चार लीटर पानी बरबाद हो जाता है। इस बरबादी को हम कैसे रोकें और इस पानी को कैसे बचाया जाए, इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। अगर हम पानी की इस बरबादी को नहीं बचाएंगे,

तो जैसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने पोखर और तालाब देखा था, हम कुंआ देख रहे हैं, हमारे बच्चे नल देख रहे हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी, इसकी चिन्ता हमें करनी होगी।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव है कि जिस तरह से स्वच्छता अभियान पर हम लोगों ने काम किया और इससे हमें कामयाबी मिली है, उसी तरह से हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी ध्यान दें। यह इसलिए कि हमारे देश में औसतन 117 सेंटिमीटर बारिश होती है, जिसमें से मात्र 6 प्रतिशत पानी का ही भंडारण हो पाता है। हमने अभी जो चुनाव लड़ा था, उसमें हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ निश्चत किया और वादा किया कि "हर घर में जल का नल" पहुंचाया जाएगा और उस पर काम चल रहा है तथा हर घर में 'जल का नल' पहुंच रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव और देना चाहती हूं। अगर वे इन सुझावों पर अमल करें, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत हद तक इस संकट से बच सकते हैं। मेरा सुझाव है कि केन्द्र के स्तर पर एक ऐसा निकाय बनाया जाए, जो पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करे, जिससे ऐसा न हो कि कोई तो 5 गैलन पानी का इस्तेमाल करे और किसी को एक बूंद पानी भी मुहैया न हो। यह निकाय देश की नदियों के पानी का वितरण भी सुनिश्चित करे। वाटर प्यूरिफायर की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ताकि उससे पानी की होने वाली बरबादी से बचाया जा सके। इसके लिए अपार्टमेंट्स आदि में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लगाया जा सकता है।

महोदय, यहां पर सिंगापुर की बात हो रही थी। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जिस प्रकार से सिंगापुर में ...**(व्यवधान)**...

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** اُپ سبھاپتی مہودے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج اس جل سنکٹ پر مجھے بولنے کا موقعہ دیا اس کے لیے میں اپنی پارٹی کا اور اپنے نیتا کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جل سنکٹ ایک ایسا سنکٹ ہے، جو ہر طبقے کے ساتھ اور ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چاہے وہ کسان طبقہ ہو یا پھر گھریلو کام دھندے کی بات ہو یا پھر پینے کے پانی کی بات ہو یا پھر عام لوگوں کی زندگی کی بات ہو یا پھر انڈسٹری چلانے والے لوگوں کی بات ہو۔

(اُپ سبھادھیکش، ڈاکٹر ستیہ نارائن جاٹیہ صدرنشیں ہوئے۔)

میں سب سے پہلے سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج آپ نے اس موضوع پر چرچہ کرائی۔ کہیں نہ کہیں آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے ہم جل سنکٹ سے جوجھ رہے ہیں۔ ہمارا دیش دنیا کا ایک اکیلا ایسا دیش ہے، جہاں پر چارموسم ہیں۔ ہمارے یہاں برسات کے موسم کی بہت اہمیت ہے۔

مہودے، ساون کا مہینہ ہو یا بھادوں کا، وہ کسانوں، عورتوں اور عام زندگی کے لئے بہت ہی خوشی لاتا ہے۔ پہلے جب عورتیں کھیتوں میں روپائی کیا کرتی تھیں، تو

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم فلاں گانا گائیں گے،تو بارش ہوگی اور ان کے ذریعے گانا گانے کے بعد، واقعی بارش ہوتی بھی تھی، لیکن اب کہیں نہ کہیں آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے ویسا ماحول نہیں ہے۔

مہودے، ناسا اور دنیا بھر کے ودّوانوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں اب اگر تیسری عالمی جنگ ہوگی، تو پانی کے لئے ہوگی۔ نیتی آیوگ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساٹھہ کروڑ بھارتیہ گمبھیر پانی کے سنکٹ سے جوجھہ رہے ہیں اور ہر سال دو لاکھہ لوگ پینے کے لئے صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے بہت گمبھیر بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔

مہودے، میں مانئے منتری جی کا دھیان اس طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، جیسا یہاں کہا گیا کہ دیش میں کئی جگہوں پر پوکھروں کو بھر بھر کر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ مگر ہمیں اس طرف بھی سوچنا پڑے گا کہ آج جو بڑے بڑے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، ان میں یا بڑے بڑے گھروں میں ہم صاف پانی پینے کے لئے جو آر۔او۔ وغیرہ لگاتے ہیں، ان سے ہمیں اگر ایک لیٹر پانی ملتا ہے، تو لگ بھگ چار لیٹر پانی برباد ہوجاتا ہے۔ اس بربادی کو ہم کیسے روکیں اور اس پانی کو کیسے بچا سکیں، اس طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ اگر ہم پانی کی اس بربادی کو نہیں بچائیں گے، تو جیسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے آباؤاجداد نے پوکھر اور تالاب دیکھے، ہم کنویں دیکھہ رہے ہیں، ہمارے بچے نل دیکھہ رہے ہیں اور مستقبل میں آنے والی پیڑھی کیا دیکھے گی، اس کی فکر ہمیں کرنی ہوگی۔

مہودے، میرے کچھہ سجھاؤ ہیں۔ میرا پہلا سجھاؤ ہے کہ جس طرح سے سوچھتا ابھیان پر ہم لوگوں نے کام کیا اور اس سے ہمیں کامیابی ملی ہے اسی طرح سے ہم رین۔ہارویسٹنگ سسٹم پر بھی دھیان دیں۔ یہ اس لئے کہ ہمارے دیش میں اوسطا 117 سینٹی میٹر بارش ہوتی ہے، جس میں سے صرف 6 فیصد پانی کا ہی بھنڈارن ہو پاتا ہے۔ ہم نے

ابھی جو چناؤ لڑا تھا، اس میں ہمارے یہاں مانئے مکھیہ منتری جی نے صاف نِشچئے کیا اور وعدہ کیا کہ "ہر گھر میں جل کا نل" پہنچایا جائے گا اور اس پر کام چل رہا ہے اور ہر گھر میں جل کا نل پہنچ رہا ہے۔

مہودے، میں مانئے منتری جی کو کچھہ سجھاؤ اور دینا چاہتی ہوں۔ اگر وہ ان سجھاؤ پر عمل کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک اس سنکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ میرا سجھاؤ ہے کہ کیندر کے استر پر ایک ایسا نکائے بنایا جائے، جو پانی کی تقسیم کو یقینی بنائے، جس سے ایسا نہ ہو کہ کوئی تو پانچ گیلن پانی کا استعمال کرے اور کسی کو ایک بوند پانی بھی مہیّا نہ ہو۔ یہ نکائے دیش کی ندیوں کے پانی کا وترن بھی سنشچت کرے۔ واٹر پیوریفائر کی پرکریا میں سدھار کیا جائے، تاکہ اس سے پانی کی ہونے والی بربادی بچ سکے۔ اس کے لئے اپارٹمنٹس وغیرہ میں ایک سسٹم بنایا جائے۔

مہودے، یہاں پر سنگاپور کی بات ہو رہی تھی۔ میں مانئے منتری جی کے دھیان میں لانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے سنگاپور میں ...(مداخلت)...

उपसभापति (डा. सत्यनारायण जटिया): श्रीमती कहकशां परवीन जी, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें। सिंगापुर की बात हो यहां हो चुकी है।

श्रीमती कहकशां परवीन: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सिंगापुर में जिस प्रकार से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे साफ करके पुन: इस्तेमाल किया जाता है, इसका अध्ययन करने के लिए यदि हमारे देश की कोई टीम वहां जाए और वहां जाकर देखे कि किस तरह से वहां पानी का सही इस्तेमाल किया जा रहा है और जो प्रक्रिया वहां अपनाई जा रही है, अगर हम भी उसी प्रक्रिया को यहां अपनाएं, तो हमें ज्यादा पानी इस्तेमाल के लिए मिल सकेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

†**محترمہ کہکشاں پروین :** مانئیہ اُپ سبھادھیکش جی، سنگاپور میں جس طرح سے بارش کے پانی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اسے صاف کرکے پھر سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ادھیّن کرنے کے لیے اگر ہمارے دیش کی کوئی ٹیم وہاں جائے اور وہاں جاکر دیکھے کہ کس طرح سے وہاں پانی کا صحیح استعمال کیا جارہا ہے اور جو طریقہ کار وہاں اپنایا جارہا ہے، اگر ہم بھی اسی طریقہ کار کو یہاں اپنائیں، تو ہمیں زیادہ پانی استعمال کے لیے مل سکے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the subject. On the issue of water, I support the statistics given by the earlier Members. While answering in Lok Sabha on 3.1.2019, the hon. Minister said that out of 17,19,000 habitations, 80.22 per cent of the habitation of the country is fully covered, that 16 per cent is partially covered and that only 3.58 per cent is left out. If it is totally covered or if 95 per cent is covered, then where is this water problem?

Out of that, two lakhs of people are dying every year due to drinking contaminated water. Sir, 70 per cent of water is contaminated. Almost 75 per cent of households do not

†Transliteration in Urdu Script.

[Dr. Banda Prakash]

have drinking water facility in their premises. Sir, 84 per cent of rural households do not have piped drinking water. Almost 22.1 per cent of the rural households have to travel more than half a kilometre distance for getting drinking water, Sir, around 21 cities in the country are facing acute drinking water problem in this country. It is affecting almost hundred million people. Sir, our country is constructing a number of irrigation projects. Sir, 100 irrigation projects were pending for about two decades. It took two decades to complete. Still 85 per cent projects are pending. The cost of the project has escalated to ₹ 1,20,772 crores.

Sir, looking at all these issues, our Telangana Government started a Noble programme called Mission Bhagiratha which was partially inaugurated by our Prime Minister, Shri Modi on 7th August, 2016. This will give piped drinking water to all the rural households of the State. It is almost covering 25,000 habitations. This will cost more than ₹ 40,000 crores. NITI Aayog also recommended sanctioning ₹ 25,000 crores to the Government of India. अभी तो project 85 per cent complete हुआ, about 15 per cent is going to be finished at the end of next month. पर सर, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक भी पैसा नहीं आया है। I request the hon. Minister to kindly look into the matter relating to Mission Bhagiratha. Kindly release the funds for drinking water for Telangana which NITI Aayog recommended. The second project that we have taken is Mission Kakatiya to restore 46,000 tanks and ponds in the State. Almost 60 per cent of the work has been completed. It will store a capacity of 265 TMC of water. Even NITI Aayog team visited our State and recommended ₹ 5000 crores grant to be sanctioned. That is also pending with the Central Government. Sir, recently on 21st of this month, our hon. Chief Ministerinaugurated the Kaleswaram Lift Irrigation Scheme. It is a very big, noble scheme. It is for the first time in the country such a big Lift Irrigation Scheme has been proposed and this was inaugurated by the hon. Chief Minister of Telangana, Shri Chandrasekhar Rao Garu. It will lift water form 98 metres to 615 metres. It will give water to almost 45000 acres for two crops in a year. It will give water supply to almost thousands of villages in the State and drinking water every day for Hyderabad city and that will also give water to all industries of Telangana. It is a Global project. It is for the first time in the country such Lift Irrigation Project is made with crores of rupees of Budget. As of today, money is paid from our State Budget. With the help of financial institutions, the project is going to be completed. Now, I request the hon. Minister; there is a demand for recognising this project as a national project. It is a Telangana project. It is a newly formed State project. I request the hon. Minister to please recognize this project as national project and immediately release ₹ 25,000 crores for this project. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri Prashanta Nanda.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, this is his maiden speech. He should be given 15 minutes.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): इसमें maiden speech मत रखिए। प्रशांत जी, अभी आप शुरू कीजिए। आपके पास अभी तीन मिनट हैं, हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे।

श्री प्रसन्न आचार्य: सर, वे पहली बार बोल रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप Short Duration Discussion में maiden speech क्यों रखते हैं? बाद में कोई दूसरी डिबेट हो, तो उसमें आप maiden speech रख सकते हैं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, यह उनकी maiden speech है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वह तो समझ में आ गया, परन्तु यह Short Duration Discussion है, तो short में long कैसे करें?

श्री हुसैन दलवई: फिर आप उनसे कह दीजिए कि यह उनकी maiden speech नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है, यह maiden speech नहीं है। आप बाद में maiden speech दीजिएगा।

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha) : Sir, it is a very, very important issue and matter of grave concern. I think, there is a little bit confusion in the discussion on the subject. We are confusing between groundwater and safe drinking water. The entire world is concerned about depleting groundwater. In India, the depletion of groundwater is a matter which has to be tackled.

Yesterday, in the Lok Sabha, hon. Prime Minister had also shown his concern on groundwater and said that we together have to solve the problem. Sir, whenever summer comes, you will find all newspapers flooded with news, basically, of drinking water shortage. And, if there is irregular rain, we get news that there is no water for agriculture! What is actually happening? We have to understand that groundwater is not an unlimited source of water; it is limited source. We have to use it and recharge it. I have seen, mostly in urban areas, people don' t care for saving water. You know you need only a cup of water for shaving. But, people open tap and start shaving without bothering how much water is wasted. Whose water is this? We are not conscious.

There was a study conducted by IIT on the depletion of groundwater. India' s northern and eastern States saw a rapid decline in usable groundwater between 2005 and 2013 raising an impending risk of severe drought, food crisis and drinking water scarcity for millions of people. A team from the IIT, Kharagpur, West Bengal, and Athabasca University, Canada, compiled first estimates of usable groundwater storage at State level across all over India using both *in situ* and satellite-based measurements.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रशांत जी, आप चाहें, तो इसको पूरा कर सकते हैं। आगे जब आप किसी दूसरे विषय पर बोलना चाहें, तो 15 मिनट का समय सकते हैं। यह पानी के विषय पर Short Duration Discussion है, पानी की समस्या पर आप बोल चुके हैं।

SHRI PRASHANTA NANDA: I was waiting for such kind words.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वैसे आपका समय समाप्त हो गया है। have taken the time allotted to you.

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, will be very brief. I will not take more time unnecessarily.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): How much time will you take?

SHRI PRASHANTA NANDA: I think, I need about 10 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Then, it will be your maiden speech.

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, you tell me how much time I can take.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): There is one more minute; only sixty seconds.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Will he get the benefit of maiden speech next time? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Yes; yes. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: It means, my next speech will be considered as maiden speech. ...*(Interruptions)*... Okay; okay. I will just sum up. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude .

...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: Let us not talk about how the depletion is happening. Let us find out solutions. So, I will be suggesting certain solutions. And, please allow me to complete this because there are only six points. Number one, one of the things that we can do to make difference is that we should use less water for luxury purposes. We must all address the issue of groundwater depletion. Considering the impending crisis on mass water service, everyone should use less water whenever possible. Water is used so freely that it is often a part of outdoor decor ideas and is used as major attractions, such as, amusement parks.

Number two, we should reduce the use of chemicals and should dispose them of properly. Many people are simply unaware of how important it is to prevent pollution occurring beneath the ground. The used water that run into the drains or sewerage system is usually laden with chemicals. These chemicals find their way into larger bodies of water, which ultimately percolates into the ground, and thereby poisons the animals and the soil. By prudent use of chemicals and their proper disposal we can check the toxic materials from dissolving in our water supply. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: More comprehensive research and additional funding can help checking depletion of groundwater. We, in Odisha, have tried our level best to check the depletion of groundwater. *(Time- Bell-rings)* Our hon. Chief Minister has been doing his best to deal with this problem. We also need Central assistance to further this cause.

One of the most effective ways to address the issue of groundwater depletion is recharging the groundwater by way of rainwater harvesting. If we don't do this. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: Sir, please give me just half-a-minute more. The indiscriminate pumping out of groundwater should be checked. This has to be regulated. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You please make your point. There is no need to explain in detail. ...*(Interruptions)*... Time is very scarce. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASHANTA NANDA: Thank you very much, Sir. I hope I will be getting more time when I will be making my maiden speech. This was my pre-maiden speech.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you, Mr. Nanda.

Now, Shri T.K. Rangarajan. You are on the panel of Vice-Chairmen. You know the rules.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a very important subject. And, through you, I would like to bring it to the notice of the hon. Minister, who is a very efficient Minister, that Tamil Nadu is suffering from: Number one, cyclone; and, second, from water scarcity. The entire delta area is highly affected. On 12th

[Shri T.K. Rangarajan]

June, they had to open the dam, but it could not be done. Two sugar factories in the delta area are closed for the past three years because the sugarcane crop has drastically come down. With this, I would like to bring to your notice that Chennai, after going dry, is perhaps the first Indian city to have approached the Central Water Commission. Till June 13, this year, Tamil Nadu has reported a rainfall deficit of 41 per cent. To meet its drinking water requirement, most of the Chennai' s population today depends on water tankers, municipal supply and private supply. A tank of water from private suppliers costs more than one gram of gold. Now gold is cheaper in Chennai than that of water. ...*(Interruptions)*... This is the truth. Sir, water the people get from the water tankers barely meets the drinking and kitchen requirements. Water sanitation is scarce. Laundry and bathing are nothing short of a luxury in today' s Chennai. The price of bottled water is reported to have gone up four times, while packaged water can only be sustained by wealthier and middle class. Sir, today, IT sector companies have asked their employees to work from their home. Several restaurants have shut down their operations. Practically, several restaurants have been shut down. The city is filled up with ' Do not waste water' billboards, stickers and banners. But, how did Chennai lose its water? All the three rivers, Cooum, Adayar, and Kosasthalaiyar are contaminated. You have to newly construct everything. Sir, North Chennai gets water from reservoir Thamaraipakkam and Minjur desalination plant. South Chennai gets water from Veeranam lake and Nemmeli sea water desalination plant. Unless you get Veeranam water, there will be no water in Chennai. Sir, Chennai used to be a water surplus metropolitan city of the country till a couple of decades ago. Following the age old water conservation tradition of Tamil Nadu, Chennai had nearly two dozen water bodies including three rivers and a British period Buckingham canal. Today, it is reduced to half a dozen. A study by Anna University has found that Chennai has lost 33 per cent of its waterlands in the last one decade. During the same period, Chennai lost in and around another 24 waterlands. This is the situation. So, it requires very, very urgent intervention from the neighbouring States which have surplus water to help Tamil Nadu and Chennai. It is very particular. Chennai is a cosmopolitan city. More than 40 to 50 per cent people are from Andhra Pradesh and from Gujarat. It is a cosmopolitan city.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Kerala.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Yes, Kerala. So other States have got the responsibility to save Chennai. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you. Now, प्रो. मनोज कुमार झा। आपके पास तीन मिनट का समय है। आप अच्छा बोलते हैं। आप अपनी बात तीन मिनट में पूरा कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को, सदन की प्रक्रियाओं को धन्यवाद कि आम तौर पर राजनीतिक ऊहापोह और मुद्दों से अलग होकर एक ऐसे विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पक्ष और विपक्ष की दीवारें गिर रही हैं। यह बहुत सुखद संकेत भी है।

महोदय, पांचवीं कक्षा में रहीम कवि का एक दोहा मैंने पढ़ा था :

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष, चून।।"

मोती और चून की बात छोड़ दीजिए, हम सब मानुष की बात करें, क्योंकि आज जब मैं चेन्नई और बुंदेलखंड में वॉटर लूट की बात सुनता हूं, तो अभी हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यह हमारे आने वाले वक्त की हकीकत है कि पूरे देश में शायद सिविल वॉर हो, जल को लेकर, पानी को लेकर, चाहे वह ड्रिंकिंग वॉटर का मामला हो या इरिगेशन वॉटर का मामला हो।

महोदय, एक वरिष्ठ पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र जी ने, जो गांधीवादी थे, उन्होंने "आज भी खड़े हैं तालाब" नामक एक किताब लिखी। मेरा मानना है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स को....मंत्री महोदय हमारे सामने हैं, नया मंत्रालय है, लेकिन आपकी जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गयी हैं, क्योंकि आपको देख कर मुझे लगता है कि नमाज छुड़वाने गये थे, रोजे गले पड़े। अभी यह जो मौजूदा संकट है, उसमें यह बहुत महती बात हो जाती है। सर, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जल रिप्लेसेबल अवयव नहीं है। हमारे टाउन प्लानर्स और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम अक्सर मॉडल चुनते हैं-शंघाई, क्योटो, लंदन। आप उन शहरों की हालत देखिए और कभी भी वैसा बनने की कोशिश नहीं करें, जिसमें हमें यह लगे कि हम खुद भी नहीं रह पाये। सर, मैं जिस इलाके से आता हूं, कोसी-मिथिलांचल का इलाका है। हमारे यहां का चापाकल आज अगर किसी के यहां शादी है, तो उसे मेरे घर से उखाड़ कर दूसरे घर में लगा दिया जाता था। किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं होती थी, वह काम लोग खुद ही कर लेते थे। आज 200-200 मीटर नीचे वॉटर लेवल चला गया है। मिथिलांचल में तालाब सूख गए हैं। उन तालाबों में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं-न-कहीं हम सबको, पक्ष और विपक्ष को, यह पड़ताल करने की आवश्यकता है कि जो हजारा मॉडल है, नव-उदारवादी मॉडल है, इसमें जल-संकट के समय बाजार की भूमिका कितनी है, क्योंकि penalty बाजार से नहीं ली जाती और बाजार बड़ी तसल्ली से कह देता है कि हम तो प्राइवेट हैं जबकि हमारा जल प्राइवेट नहीं है। यह हमारी थाती है, सबकी थाती है। अगर उस जल का दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके लिए penal provisions की भी ज़रूरत है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जल संकट है। कल यही खाद्य संकट में तब्दील होगा, क्योंकि पानी का सीधा रिश्ता खाद्य से है, फूड से है। कहीं ऐसा न हो कि फूड सिक्योरिटी की बात करते-करते हम food insecurity की तरफ चले जाएं। शुक्रिया, सर, घंटी मत बजाइए। थैंक यू, जय हिन्द!

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): समझदार को इशारा काफी है और आप समझदार ही हैं। ...**(व्यवधान)**... श्री अनिल देसाई।

SHRI ANIL DESAI (Maharasthra): Sir, we are discussing a very serious subject of water crisis and, I think, distinguished MPs have expressed their views as to how serious the water crisis is. Particularly, in last couple of years, it is assuming serious proportions. This is what we have seen. As we are dependent on monsoon, due to failure of monsoon, water crisis has really aggravated in various States. So is the situation in my State of

[Shri Anil Desai]

Maharashtra also. महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ ऐसे रीजन हैं जहां come summer and people start deserting their houses and they migrate from places to places. जब वे किसी district या दूसरी जगहों पर जाते हैं, कुछ उदरपूर्ति के लिए, livelihood earn करने के लिए तो जाते ही हैं लेकिन सबसे ज्यादा उनके सामने पानी की समस्या रहती है। यह proportion इतना बढ़ गया है कि न जाने, it is said now that tomorrow's wars will be fought not on any other issue but only on water. मराठवाड़ा ऐसा रीजन है जहां पिछले कुछ वर्षों में, ऊपर के जिलों जैसे नगर है, नासिक है, मराठ्वाड़ा के 8 districts में पानी की गम्भीर समस्या को कम करने के लिए सरकार ने यह decision लिया था कि पानी ऊपर के डैम से नीचे छोड़ा जाए लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि वहां लोग आपस में इतना टकराने लगे कि एक दूसरे की जान लेने तक उतर आए। So, this situation is aggravating by the day and Government needs to take cognizance of this. परसों ही जब इस स्थिति पर assessment was taken regarding the drought situation in Maharashtra, the hon. Chief Minister of Maharashtra has immediately pumped in some 8,000 odd tankers. 8000 पानी के टैंकर्स लगा दिए कि इस समस्या को हल करें so that we come over this issue of water crisis. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में और खासकर हमारे मराठवाड़ा, विदर्भ और सेंट्रल महाराष्ट्र के जिलों में आज अकाल और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। आज जून की 26 तारीख हो गई है लेकिन अभी मानसून वहां उतना एक्टिव नहीं हुआ, जितना होना चाहिए। इस समस्या को देखते हुए, मैं दरख्वास्त करूंगा कि अभी जिस जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हुआ है, उनका दायित्व रहेगा कि महाराष्ट्र में जो पुराने irrigation projects थे, जो किसी वजह से पूरे नहीं हो सके, उन्हें बढ़ावा देने के लिए Central Government needs to give some kind of boost; some kind of arrangement needs to be done with the State Government.

(श्री उपसभापति *पीठासीन हुए)*

यहां बताया जा रहा रहा है कि climate change की वजह से these issues are happening. Water crisis will be grave in times to come. Water management needs to be done. अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यही कहा है कि किस तरह का वॉटर मैनेजमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से - 'Charity begins at home.' हम जिस पानी को use करते हैं, in 'Water usage by ourselves', we need to see that how that will be conserved, how minimum usage can be made. And that could be way of word-to-mouth orthe Government could start some drives and awareness programmes जिससे लोगों में यह अवेयरनेस हो कि पानी की हर बूंद कितने महत्व की है।

Sir, joining of States' rivers of river interlinking programme needs to be accelerated. यह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ ही हम समुद्र के पानी का desalination करके कुछ हद तक पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, otherwise in the coming days, this situation would aggravate. This should not lead to disputes with, leave apart our neighbouring countries, but even within the country, as we have witnessed in Maharashtra where when it came to giving waters to some districts that were drought-sticken, people gave all priority to sticking to the possession of their water and they said, 'whatever is my water is my water.' That should not be the case. Some kind of civic sense

also needs to be developed in the people and we need to collectively come over this water crisis. मैं समझता हूं कि जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण होने के बाद आपने जो दायित्व नए मिनिस्टर को दिया हुआ है, वह इस चीज को समझ करके आने वाले दिनों में अपने भारतवर्ष के लिए, सभी स्टेट्स के लिए आज पानी की जो समस्या है, वह पानी की समस्या कल न रहे, इस तरह का प्रबंध करेंगे, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: मैं डी. राजा साहब से आग्रह करूं, पर राजा साहब हैं, इसलिए पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यह हम सब जानते हैं और Short Duration Discussion के तहत इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो ढाई घंटे की होती है, आधा घंटा मंत्री जी का जवाब। सवा तीन बजे यह बहस शुरू हुई, इसलिए सवा पांच बजे तक इसको conclude करना है। अभी बहुत सारे स्पीकर्स के नाम हैं, पर हर समूह से एक-एक व्यक्ति बोल सके, यह कोशिश है। Otherwise हम बहस conclude नहीं कर पाएंगे, इसलिए समय के लिए हमारी विवशता होगी। जो स्पीकर्स छूट जाएंगे, यह उन दलों के लिए भी....., क्योंकि उन दलों के व्यू आ जाएं, यह कोशिश है। इसलिए राजा साहब, my request is, please take only three minutes. I hope that request would be kept in mind.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, the Prime Minister, in his speech today, referred to water crisis in 226 districts, which shows the seriousness of this problem. There is drought in many parts of the country. Sir, Tamil Nadu is one State which is passing through unprecedented water crisis. There is drinking water crisis in major cities like Chennai and several villages. People are agitating, carrying empty pots in their hands, demanding water supply. There is unrest in the State of Tamil Nadu. In this regard, I would like to make a few observations. One, despite rainwater harvesting, despite conversion of sea water into drinking water, Chennai is facing a severe drinking water crisis. Tamil Nadu is one State which has problems of river water, because except one river, all other rivers are inter-State rivers. So, there are inter-State river water disputes. The Centre should see to it that these disputes are settled in a fair manner. Riparian States should have equal rights. For instance, Tamil Nadu is a lower riparian State as far as Cauvery and Palar are concerned and it should be ensured that Tamil Nadu gets equal rights on these rivers. It should get a fair share because there is a crisis. There is no water for irrigation and no water for cultivation. What would Tamil Nadu do? Delta districts have become drought-prone districts. Famine conditions are emerging. This is a serious problem. So, Centre should address the inter-State river water issues. Whether you do it through NITI Aayog or the Ministry, the time has come when inter-linking of rivers must be discussed at the national level and there must be efforts to evolve a national consensus. It is not a simple issue. We should try to evolve a national consensus. Linking of rivers must be given adequate attention and there must be a national level discussion on this. Sir, we have a system of lakes, ponds and everything, but we don' t preserve and conserve them. But preservation and conservation of water bodies is to be taken up on a priority basis. There are encroachments. There are several judicial verdicts that encroachment should be removed. But whenever we talk of enoroachments, people always think that it is the poor who go

[Shri D. Raja]

and occupy the lake side or river side. The targets are always the poor. But it should not be the approach. The corporate houses, land mafias, and even Government agencies encroach upon the water bodies and construct buildings. How to address this issue? The blame should not be on poor people. Poor people can go because they live in huts. Any time you ask them, they will go.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, please conclude.

SHRI D. RAJA: Sir, I am finishing. This issue should be addressed. Moreover, we are living in a time when global warming has become a global issue; environmental changes have become global issues. In such a background, how to address the question of water? Water management must be a primary priority of both the Central Government and the State Governments. Preservation of forests must be another area of concern and the Government will have to address this also. With these suggestions, I conclude.

श्री उपसभापति: मैं अब माननीय ओम प्रकाश माथुर जी को आमंत्रित करूंगा। उनकी maiden speech अभी नहीं हुई है। मैंने समय देखते हुए आग्रह किया है कि बहुत कम समय में वे अपना सुझाव दें, ताकि अधिक से अधिक लोग सवा पांच तक बोल लें। यह हमारी कोशिश होगी। आप pointed suggestions दें।

श्री ओम प्रकाश माथुर (राजस्थान): उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि आजादी के 71 वर्षों के बाद उन्होंने पानी की चिंता के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया। मैं उस प्रदेश से आता हूं, जो पानी की समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानता है।...**(व्यवधान)**...हमारा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री जी ने भी एक ऐसे लाल को उस मंत्रालय का दायित्व दिया है, जिसने अपने पढ़ाई के काल में भी और अध्ययन के बाद भी उस क्षेत्र को बहुत बारीकी से देखा है, घूमा है, भ्रमण किया है। मैं हमारे मरू प्रदेश की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। यह आम मान्यता है कि मरू प्रदेश को भगवान कृष्ण का एक वरदान है कि मरू प्रदेश में कभी भी जल की कमी नहीं रहेगी, लेकिन उस वरदान को मानकर मरू प्रदेश के लोग या राजस्थान के लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ गए। उन्होंने कई तरह के उपयोग किए। मैं उन उपयोगों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ गिनवाना चाहता हूं, जैसे तालाब, झीलें, नाड़ी, बावड़ी, टांका, झालरा, टोबा, खड़ीन। गजेन्द्र जी खड़ीन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे शेखावटी में पहले कोई भी ऐसा मकान नहीं रहता था, जहां छत पर पानी इकट्ठा नहीं किया जाता था और उसे साल ही नहीं, लगातार सालों तक उसका उपयोग drinking water की तरह करते थे। उसमें कभी कोई खराबी नहीं आती थी, न ही कोई aquaguard की जरूरत रहती थी। आज भी शेखावाटी में लगभग 20-30 परसेंट ऐसे घर हैं, जो वर्षा के पानी का drinking water की तरह उपयोग करते हैं। आखिर वह भी तो कोई कला थी, लेकिन आज दुर्भाग्य है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में एक कहावत है, सैकड़ों-हजारों तालाब अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, इनके पीछे एक इकाई थी, बनवाने वालों की, एक दहाई थी, बनाने वालों की, एक इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों हजार बनाती थी, परंतु दुर्भाग्य है कि पिछले 200 वर्षों में लोग नए किस्म की थोड़ी-सी पढ़ाई ऐसी पढ़ गए कि समाज ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को बिल्कुल खत्म करके पानी

5.00 P.M.

को शून्य कर दिया। मैं आपको पानी का महत्व बताना चाहता हूं।

हमारे यहाँ जो तालाब खुदता था, तो ऐसा नहीं है कि उसे केवल गांव के लोग ही खोदते थे। मैं गजेन्द्र सिंह को याद कराना चाहता हूं, वे खुद जैसलमेर गए हैं। जैसलमेर में जो गढ़ीसर तालाब बना है, उस तालाब की खुदाई गांव के लोग इकट्ठे करते थे, लेकिन राजा भी प्रतिदिन उस तालाब पर जाता था, चाहे वह वहां आधे घंटे के लिए ही जाता था, लेकिन वह वहां जाकर स्वयं मजदूरी करता था। मैं इससे आगे एक बात बताना चाहता हूं। उससे प्रभावित होकर राजा के महल में जो नृत्यांगना थी, उसको जल के प्रति महत्व महसूस हुआ और उसने पिछले सालों की सारी कमाई उस गढ़ीसर तालाब की खुदाई में लगाई और वहां इतना सुन्दर गेट बन गया कि वह आश्चर्यजनक गेट वहां आज भी विद्यमान है, उसे आप देख सकते हैं।

उपसभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मैं ब्रिटिश काल की एक घटना बता रहा हूं। जब रेलवे लाइन बिछने लगी, तो उदयपुर में रेलवे लाइन बिछी, लेकिन रेलवे लाइन उदयपुर के तालाब के ऊपर से गुजरी। कुछ दिनों बाद उस तालाब की दीवार, जिसको पाल बोलते हैं, उसमें एक crack आ गया। मैं उस समय के राजा राणा भोपाल सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय, आजादी से पहले ब्रिटिश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उस तालाब को उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट को ठीक कराना पड़ा। आपने पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय को लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आज इस पर राजनीति से हटकर डिबेट हो रही है।

अभी शिव सेना के हमारे मित्र बोल रहे थे और भाई मनोज कुमार झा भी बोले उन्होंने अनुपम मिश्र का जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को अनुपम मिश्र द्वारा जल संरक्षण पर लिखी गई सारी पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

मैं अपने क्षत्र की दो विशेष बातें बताकर बैठ जाऊंगा और आपने समय के बारे में जो आदेश दिया है, उसको मानूंगा। हमारे क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जवाई बाँध है। वह लगभग हजारों गाँवों को irrigate करता है और वह सैकड़ों गाँवों में drinking water पहुंचाता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। Rainfall कम होने की वजह से 10 सालों में वह सिर्फ चार साल भरता है और छः साल खाली रहता है। मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार उसके पीछे लगा हूं। मैंने दो डैम ऊपर बनवाए, फिर भी काम नहीं बना। आखिरकार, नरेन्द्र भाई की पिछली बी.जे.पी.-एन.डी.ए. की सरकार बनने के बाद सेंटर ने हमको पांच स्कीमें दीं। उन पांच स्कीमों में से एक स्कीम उस जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से आज यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय उसी क्षेत्र से आते हैं। उससे जोधपुर भी पानी जाता था। वह आजादी के पहले का डैम है। जैसे, अभी इन्होंने एक प्रश्न किया कि पुनर्भरण या water harvesting के लिए क्या काम किया जाए? अगर वह स्कीम इम्प्लिमेंट हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वह स्कीम अवार्ड हो चुकी है और उसको जल्द पूरा किया जाए।

एक और चीज़, जयपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले रामगढ़ बांध से पूरा जयपुर पानी पीता था। 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में पानी के सारे गेम्स वहां रामगढ़ बांध में ही हुए। क्षमा करेंगे, मैं कहूँगा कि अगर आपको इतनी चिन्ता हो रही है, तो कुछ न कुछ अधिकारियों पर भी शिकंजा

[श्री ओम प्रकाश माथुर]

लगना चाहिए। भराव क्षेत्र में जितना अतिक्रमण है, वह सारा अतिक्रमण इन अधिकारियों के माध्यम से हुआ है। मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का 2017 में आदेश आया हुआ है कि जितने अतिक्रमण हो रहे हैं, उनको तोड़ा जाए। इसके लिए कहीं न कहीं अधिकारी जिम्मेवार हैं। वे पता नहीं कैसे जवाब देते हैं। आप कम से कम ये दो काम करें।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माथुर साहब।

श्री ओम प्रकाश माथुर: मैं अब बैठ रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अगर ये दो काम करेंगे, तो जयपुर तथा पूरे राजस्थान को फायदा होगा। मैं अपने साथ ये चार किताबें लेकर आया हूं। मैं आपको आखिर में यह बता देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे फॉर्म पर आए हुए हैं। मैं खुद वॉटर हार्वेस्टिंग करता हूं, बहुत अच्छा किसान हूं। मैं 100 बीघा जमीन में rain water इकट्ठा करके irrigation करता हूं। अगर कोई यह प्रयोग करना चाहे, तो जनता को सहयोग मिलना चाहिए। एक किसान किस प्रकार से अपनी धरती पर यह करे, यह सोचा जाना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: मैं माननीय हुसैन दलवई जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले सिर्फ सूचना के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि आप सब राजनीतिक जीवन में हैं और पानी का संकट देश में बहुत गंभीर है। आपने बहुत सही मेंशन किया कि राजस्थान में पुरानी टेक्निक क्या थी। इस देश में पानी पर काम करने वाले बहुत लोग हुए, जिनमें से एक अनुपम मिश्र जी भी थे। वे भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि गांधीवादी थे, उनके लड़के थे। उनकी पुस्तक दुनिया भर में बिकी। शायद उस पुस्तक का नाम "राजस्थान की रजत बूंदे" है। उसमें यह बताया गया है कि पुराने दिनों में rare techniques क्या थीं। हम शायद उससे सीखकर अपने देश के कोने-कोने में यह बता सकते हैं कि उस तरह की तकनीक से हम कैसे पानी बचा सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश माथुर: सर, आपने भी इस पर कई लेख लिखे हैं, जिन्हें हमने पढ़ा है।

श्री उपसभापति: जी, धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई : महोदय, आज आपने एक अच्छा विषय चर्चा के लिए चुना है। ऐसा कहा जाता है कि "जल है तो कल है।" महाराष्ट्र में पिछले तीन-चार साल से अकाल है। वहां लोगों को पीने के पानी की बड़ी समस्या है। उसमें भी मराठवाड़ा और विदर्भ का कुछ भाग, अमरावती के इलाके में बड़ी दिक्कत है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि मैं कोस्टल एरिया, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। महाराष्ट्र में जो बारिश होती है, उसमें रत्नागिरी और कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन हर साल कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी फरवरी से नहीं मिलता है और टैंकर्स चलाने पड़ते हैं। कहीं न कहीं इसका हल होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से ठीक ढंग से इसके ऊपर काम होगा तो सफलता मिल जाएगी।

महोदय, मराठवाड़ा में 45 मेजर डैम्स हैं, 2.77 परसेंट live water storage है, तो भी Paithan, Manjara, Lower Terna, Siddheshwar और Majalgaon में पानी की बिल्कुल स्टोरेज नहीं है, यह बड़ी गंभीर बात है। बीते वर्ष 396 वॉटर टैंकर्स चलते थे, लेकिन आज उन टैंकर्स की संख्या 2,359 हो गई है और 2,348 गांव ऐसे हैं, जहां पानी की बड़ी समस्या है। आज 1.87 करोड़ लोग पीने के पानी की मुसीबत में पड़े हुए हैं। मवेशी की स्थिति तो ऐसी है कि हमारे कुछ मित्र सतारा जिले में मान तालुका में जानवरों का कैम्प चलाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि आप सिर्फ तीन हजार जानवर रख सकते

हैं, लेकिन वहां 12 हजार जानवर हैं। उनका कहना है कि हम बंद कर देंगे, आपको जैसे चलाना है, वैसे चला लीजिए। वहां मंत्री जी को जाना पड़ा कि ठीक है, हमारा नियम ऐसा है कि तीन हजार जानवर रख सकते हैं, लेकिन आप अगर बंद कर देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बंद मत कीजिए, हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन उनकी ठीक ढंग से मदद नहीं हो रही है। मेरा कहना ऐसा है कि कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की कार्य योजना में पानी का सवाल सबसे अहम बनाना बहुत जरूरी है। पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए। आज कल बोतल के पानी का फैशन निकला है, गरीब लोग बोतल नहीं ले सकते। हर आदमी को कम से कम शुद्ध पानी मिले, यह देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि पानी की स्टोरेज कैसे बढ़ेगी।

महोदय, मैं एक सुझाव दूंगा कि हमारे सांसदों को जो एम.पी.लैड फण्ड मिलता है, अगर शुद्ध पानी देने के लिए गांव-गांव में उसकी सुविधा बनायी जाए, अगर उसकी परमिशन मिले तो यह बहुत बड़ा काम होगा। मैं ऐसा सुझाव देता हूं और मेरा कहना है कि कम से कम शुगरकेन के बारे में भी सोचना चाहिए। जहां बड़े पैमाने पर पानी आता है, वहां शुगरकेन होता और फिर अकाल वैसा का वैसा ही रहता है। हमारे यहां साइनाथ जी ने इसके ऊपर बुक लिखी है 'Everybody Loves a Good Drought' वहां टैंकर्स चलते हैं, टैंकर्स की बड़ी लॉबी है। यहां जावडेकर साहब बैठे हैं, उनको मालूम है कि टैंकर्स कैसे चलेंगे, वैसे ही देखा जाता है। अगर टैंकर्स निकाल रहे हैं, तो कम से कम ठीक ढंग से पीने का पानी हर जगह मिले, ऐसा देखना बहुत जरूरी है। मैं एक सुझाव दूंगा।

श्री उपसभापति: दलवई जी, धन्यवाद।

श्री हुसैन दलवई: शुगरकेन की बजाय बीज का प्रोडक्शन किया जाएगा तो शुगर की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी और उसके लिए पानी की जो जरूरत, उसमें 50 परसेंट कम पानी लगता है। उससे शुगर फैक्ट्री भी चल सकती है और शुगर का प्रोडक्शन भी हो सकता है, इसका भी सरकार को विचार करना चाहिए, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए धन्यवाद। माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी, आपके दल का समय तो समाप्त हो गया है, किंतु आप बुंदेलखण्ड इलाके से आते हैं, किंतु आप बुंदेलखण्ड इलाके से आते हैं, जहां देश की अन्य जगहों की तरह बड़ी गंभीर समस्या है तो आप बहुत कम समय में वहां की समस्या बताएं और यह भी बताएं कि concrete सुझाव के साथ क्या किया जाना चाहिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, पेयजल संकट को दूर करने के लिए जो अल्पकालीन चर्चा हो रही है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, मैं अपने को उससे संबद्ध करते हुए दो-तीन सुझाव यहां देना चाहता हूं। महोदय, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग है। वहां वॉटर लेवल करीब 22 मीटर से 50 मीटर तक नीचे चला गया है। बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, ये जो एरियाज़ हैं, वहां की बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि वहां पर रिज़र्व वॉटर की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए...क्योंकि वहां वर्षा आधारित डैम है, जिससे पेयजल की सप्लाई होती है। वहां वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए, जो पुराने डैम बने हुए हैं, उनकी मरम्मत करना और उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे इलाके में बुंदेलखंड क्षेत्र की एक खण्डे पेयजल योजना है। मान्यवर, जनपद हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में कपसा एक गांव ऐसा है, वहां पर कोई भी अपनी लड़की की शादी इसलिए नहीं करता है, क्योंकि

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

उनको कुएं से पानी लाना पड़ता है। गांव से दो किलोमीटर दूर खेतों में कुआं है। वहां पर रात तीन बजे से लाइन लगती है और जो भी सुबह जल्दी जाता है, तो वह कुएं से मीठा पानी निकाल लेता है। बाकी वहां कहीं भी मीठा पानी नहीं है, यह समस्या है। उसके लिए उपाय करने चाहिए। वहां पर हैंड पम्प सूख गए हैं, कुएं सूख गए हैं, वहां पर बड़ी मुसीबत है। पाठा क्षेत्र की एक कहावत है। पाठा क्षेत्र में जो जलाशय, गड्ढे हैं, वहां लोग सुबह पहुंच जाते हैं, वे पानी भर लेते हैं। वहां की कहावत है, "हमारी गगरिया न फूटे खसम चाहे मर जाए।"

यह कहावत है कि पानी इतना महत्वपूर्ण है। हमारा सुझाव यह है कि पेयजल संकट को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए। मेरी केन्द्र सरकार से गुज़ारिश है कि पानी को बचाने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पानी बचाने के प्रति भावना पैदा हो। आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा, तो पानी के लिए होगा। हमारे उत्तर प्रदेश मे खास तौर पर बुंदेलखंड में नदियां हैं, जिनमें केन नदी, बेतवा, यमुना, उर्मिल बागेन, चन्द्रावल, गुन्ता, बरदहा, रंज, मंदाकिनी, धसान, वयस्विनी नदियों में बालू माफियाओं द्वारा नियमों को ताक में रखकर अवैध बालू/मोरम का खनन किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: निषाद जी, आपके दो मिनट पूरे हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: ये नदियां हैं। मान्यवर, सिर्फ दो मिनट। यहां पर जो खनन हो रहा है, वह एन.जी.टी. के नियमों के विरुद्ध 20-20, 40-40 फुट तक गड्ढे करके नदी में बांध बनाकर गहरी नदियों की धारा पलट देते हैं, जिसके कारण वहां पर वॉटर सप्लाई की जितनी स्कीम्स हैं, वे सब फेल हो गई हैं। उनमें पानी नहीं जा रहा है। पेयजल का संकट हो गया है। वहां बाहर से जो टैंकर आते हैं, तो जो दबंग व्यक्ति हैं, वे रात में उसे पूरा लूट लेते हैं। हमारा सुझाव है कि वहां पर जो अवैध खनन हो रहा है, जो एन.जी.टी. के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए और नदियों को बचाने का काम करना चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। मेरा यही सुझाव है कि जो ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, इसके बारे में केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए। बुंदेलखंड हमारा बहुत ही पीड़ित क्षेत्र है। वहां बांदा में, चित्रकूट में और महोबा में इस समय पानी का घोर संकट है। उसके लिए प्रदेश सरकार भी काम कर रही है और हम केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगे कि वहां एक आयोग बना है, अलग से विभाग बना है, तो वहां के लिए स्पेशल बजट देकर, वहां की पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the next speaker is Shri R.S. Bharathi of the DMK party but, before that, अभी तक लगभग इसमें आठ स्पीकर्स बचे हुए हैं। मेरी आपसे request होगी कि यदि आप सब सहमत हों, तो सब को दो-दो, तीन-तीन मिनट concrete suggestions के लिए we can give time. अगर सरकार जवाब के लिए सहमत हो.... तो मंत्री जी, आपको जवाब के लिए आधे घंटे का समय चाहिए। 5.15 बजे तक बहास कन्क्लूड करनी थी, but there are some Members who want to speak.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, since this is an important issue and if the Members are

willing to speak, I think we should allow them to speak.

SHRI R.S. BHARATHI (Tamil Nadu): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important topic that has to be discussed by this august House. All my previous speakers have mentioned about the water scarcity that the country is facing. As many of them have pointed out, by the year 2020, 21 cities in India will have no ground water and by the year 2030, 40 per cent of the country will have no ground water. Sir, this is an alarming information.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair]*

So, it is high time to chart out all these problems. Due to paucity of time, I would like to mention four or five points only.

First of all, I would request the Central Government to link the rivers. It has been stated in your manifesto but in the President' s Address, there is no mention of linking of rivers. I would like to request the Government of India to, at least, link the rivers which are in south India because Tamil Nadu, especially, Chennai, which has a population of more than one crore and eleven lakh people, is without water. Children are not able to go to schools. Office-going women are on the streets waiting till midnight for getting water by tanker lorries. This has to be taken note of, and, I would suggest that the Government, though it has formed a Ministry, should put this issue on its agenda and first priority should be given to linking of rivers in south India. Sir, we face two kinds of situations, one is, cyclone or floods and the other is drought. So, to get over this crisis, the only solution would be linking of rivers. This has been repeatedly mentioned by all the Members but the, Centre does not seem to care for it. At least, now when the Government has formed a separate Ministry, I hope, this issue will be given top priority.

I was the Municipal Chairman for four terms in Alandur. Sir, people are prepared to pay if you do something. I implemented one underground sewerage project under the PPP (Public-Private Partnership) model. We collected 5,000 rupees as deposit and people deposited that amount. Why I am mentioning this is because we will have to pay something for getting water also. In Chennai, there are so many quarried hills, which have grey and black water. It is going waste and all the rainwater during monsoon goes into the sea. This has to be rationalised and water has to be stored.

As rightly mentioned by senior colleague, Shri T.K. Rangarajan, there was a time when Pachaiyappa Mudaliyar took bath in Cooum river but today it is a contaminated river. Please remove all this contamination.

Sir, I do not have time but I would conclude by making one request to the Central Government to kindly include ' water' in the Concurrent List, and, instead, you put

[Shri R.S. Bharathi]

' education' in the State List. The issue of education is causing so many problems in Tamil Nadu. People are agitated over NEET and other things. So, please put ' education' in the State List and take 'rivers and water' in the Concurrent List. With these words, I conclude. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Bharathi. Now, Dr. Ashok Bajpai.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने ऐसे गंभीर विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज देश के सभी भूभागों में पेयजल की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज स्थिति यह है कि 65 मीटर गहराई में ground water मिल रहा है, लेकिन आने वाले दस वर्षों में यह गहराई 100 मीटर हो जाएगी, 100 मीटर से नीचे पेयजल मिलने का काम होगा। अगर आप देखें तो आज जितने भी महानगर हैं, उनमें सभी जगह आने वाले दिनों में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न होने वाला है। जिस तरह से भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है, वह एक चिंता का विषय है। मान्यवर, हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची में यह एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए हमें राज्यों को पूरी तरह से विश्वास में लेकर ऐसी नीति बनानी होगी, जिससे हम जल संरक्षण कर सकें।

मान्यवर, आप देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई के लिए इतने अधिक जल का दोहन हो रहा है कि उससे भी हमारा ground water निरंतर नीचे जा रहा है। आज सिंचाई की जो नयी तकनीक है, चाहे sprinkler से हो या drip water से सिंचाई की तकनीक हो, हमें नयी तकनीक से कम से कम पानी से खेतों की सिंचाई करनी होगी क्योंकि सिंचाई में बहुत अधिक मात्रा में हमारा भूगर्भ जल बरबाद हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हम कैसे वर्षा के जल का संरक्षण करें? दूसरी बात यह है कि हम कैसे वर्षा के जल का संरक्षण कर सकें, इसके लिए सरकारों को कठोर नीति अपनानी होगी। जो घरों के नक्शे पास होते हैं, उसके साथ इतना ओपन एरिया छोड़ना होगा, जिसमें कि वर्षा के पानी का संरक्षण हो सके, वह percolate कर सके, पानी नीचे तक जा सके, तो ground water के रूप में restore हो सके। आज स्थिति यह हो रही है कि सारे concrete के जंगल शहरों में बनते जा रहे हैं। एक इंच भी कच्ची जमीन नहीं रहती है, जहां पर जाकर ground water या rain water harvesting का काम हो सके। पहले छतों के ऊपर जो यह प्रयास हुआ था कि छतों के ऊपर भी छतों के पानी को संचित किया जा सके, इस संचयन की दिशा में हमारे नगर विकास विभाग को कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। हम प्रत्येक घर की छतों में कैसे rain water harvesting कर सकें, इस दिशा में भी हमको काम करने की आवश्यकता है। छोटी-छोटी नदियों के ऊपर और जो छोटे-छोटे बरसाती नाले हैं, उनके ऊपर counter-dam, check dam बनाकर और उस पानी को रोक कर, उस पानी का percolation हो और भूगर्भ जलस्तर बढ़े, इस दिशा में भी काम करना होगा। पहले गांव में तालाब हुआ करते थे, लेकिन भूमाफियाओं ने उन तालाबों पर ऐसा कब्जा कर दिया कि धीरे-धीरे तालाब पाट कर के उन पर मकान बनते जा रहे हैं। कड़ाई के साथ इन तालाबों का संरक्षण होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हर बसावट के ऊपर और गांव सभा के अंदर एक कोटा निर्धारित हो कि इतनी आबादी पर, इतने एरिया में, इतने तालाब जरूर होंगे और उन तालाबों को बनाते समय भी technically उसकी feasibility को देखा जाए। जैसे होता यह है कि ऊंचाई की जगह पर तालाब बना दिया गया है और पानी की ढलान नीचे की तरफ है, तालाब में पानी ही नहीं जाता

है और केवल सरकारी पैसे का ही अपव्यय हुआ, तालाब बना खड़ा है और बरसात में भी वह सूखा रहता है। तालाब ऐसी जगह पर हो जहां पर वर्षा का पानी उसमें एकत्र हो सके। तालाबों के संरक्षण से, पोखरों के संरक्षण से, जो जलाशय हैं, water reservoirs हैं, उनके संरक्षण की महती आवश्यकता है और इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। आज नदियों की स्थिति बड़ी चिंतनीय है। देश की तमाम नदियों में जल स्तर निरंतर गिर रहा है और उनके भी सूखने की संभावना है।

मान्यवर, नदियों को भी कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर भी एक बृहत् कार्य योजना बने, क्योंकि आने वाले दिनों में पेयजल का गंभीर संकट होगा। आजादी के समय हमारे पास प्रति व्यक्ति पांच हजार घन लीटर पानी उपलब्धता थी और आज स्थिति है कि अब एक हजार घन लीटर पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है। इस उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हम जब तक भूगर्भ जल का संरक्षण नहीं करेंगे और जब तक वर्षा के पानी को हम संरक्षित नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या से निजात नहीं मिलेगी। इसके लिए एक देशव्यापी बड़ी योजना बने और मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया और जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की। यह निश्चित रूप से उनकी प्राथमिकता है और जल शक्ति मंत्रालय इस विषय में ठोस कदम उठाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद, माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। मान्यवर, भारत में जल संकट 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित और पल्लवित हुई हैं। अधिकांश प्राचीन नगर जो develop हुए हैं, वे नदियों के तट पर ही हुए हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के सर्वोच्च सदन में और देश के बाहर भी समय-समय पर तमाम इस तरह की गंभीर समस्याओं पर चर्चा होती रही है, चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, छुआछूत हो, प्रदूषण हो, शिक्षा हो, जनसंख्या वृद्धि हो या जल संकट हो, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी ये समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि जल संकट जैसी विकराल समस्या पर इस सदन में जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, यह केवल चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर, ईमानदारी के साथ इस समस्या से निपटने के लिए कोई गंभीर योजना बनाने का काम करें। अगर हम लोग इस पर गंभीर योजना बनाएं और जिस तरह के सुझाव हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा, बड़े सदस्यों के द्वारा आए हैं, अगर हमने उन सुझावों पर चर्चा करने का काम किया, उन पर अमल करने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि जल संकट से निपटा जा सकता है। जैसा कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि देश की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले दशक यानी 2030 से पहले तक भारत जल संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएगा। विश्व बैंक की उस रिपोर्ट को नजरअंदाज़ करना बेमानी होगा, जो कहती है कि जलवायु परिवर्तन और बेतहाशा पानी के दोहन की मौजूदा आदत से बहुत जल्द देश भर के 60 फीसदी वर्तमान जल स्रोत सूख जाएंगे। कल्पना कीजिए कि अगर हमारे 60 परसेंट जल स्रोत सूख गए, तो क्या होगा। आजकल गांवों में पानी के लिए मारा-मारी होती है, यहां तक कि हत्या तक हो जाती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पानी की कमी आने वाले समय में विकराल रूप धारण कर लेगी।

मान्यवर, जिस तरह से पानी की समस्या 2030 तक बढ़ रही है, हमें आपूर्ति के हिसाब से दो गुना पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की रिपोर्ट भी हमें डराती है, जिसमें जल संकट को 10 अहम खतरों में सबसे ऊपर रखा गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जब प्यास मनुष्य को पलायनद करने के लिए मजबूर कर दे, तो विकास की बात करना बेमानी बात होगी। मान्यवर, सरकार ने जल

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। उस मंत्रालय के माध्यम से यह कहा है कि हम अगले पांच सालों में हर गांव के घर में नल से पीने का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यह सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन कहीं यह पिछले वायदों की तरह, जैसे कहा गया था कि 15 लाख रुपये हर गरीब के खाते में आएंगे, यह जुमला न हो। मैं इसके संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर बारिश के पानी को पांच परसेंट भी संचयित कर लिया जाए, तो साल भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की पानी की सारी जरूरतें पूरी कर ली जाएंगी। मैं इस सुझाव के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जो 70 परसेंट पानी है, उसमें मात्र तीन परसेंट मीठा पानी है, उस पानी की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और इसके लिए सरकार को ठोस योजना बनानी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लाल सिंह वड़ोदिया (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पीने का पानी और सिंचाई का पानी दोनों की जितनी जरूरत है, उसके हिसाब से आज की तारीख में पानी की कमी पड़ रही है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जितने पानी की उपलब्धता थी, उसके हिसाब से 2020 में यह उपलब्धता सिर्फ 25 परसेंट रह जाएगी। पहले भी कई सरकारों ने विवेकतापूर्वक पब्लिक को कहा और वह काम पब्लिक ने स्वीकार भी किया था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक टाइम का भोजन छोड़ दो, तो लोगों ने छोड़ दिया था। हमारे नरेन्द्र भाई मोदी ने कहा कि सम्पन्न लोग सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ दें, तो लोगों ने सब्सिडी लेना छोड़ दिया। ऐसे ही गजेन्द्र सिंह जी से मेरी विनती है कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए हरेक गांव में चार भागों में चार तालाब होने चाहिए, यह सुनिश्चित करें। बारिश का जो पानी गिरे, वह तालाबों में गिरे और उससे वॉटर लेवल बढ़ जाए। हरेक घर की छत पर जो बारिश का पानी गिरता है, उसको इकट्ठा करके अंडर ग्राउंड टैंक में रखना चाहिए। मैंने आज ही वाट्सऐप पर देखा था कि अगर 100 स्क्वायर फीट की छत हो और उस पर करीब 100 सेंटीमीटर यानी 40 इंच की बारिश होती है, तो एक लाख लीटर पानी उस छत से टैंक में रिजर्व किया जा सकता है। पांच आदमी के एक कुटुम्ब को पीने के लिए एक साल में 10,000 लीटर पानी की जरूरत रहती है। इस प्रकार एक लाख लीटर से दस परिवारों के लिए पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा।

हमारे गुजरात में 100 साल पहले भी जो सम्पन्न लोग थे, वे अपने घर में ही उस स्टोरेज टैंक बनाते थे और बारिश का पानी उसमें स्टोर करते थे, तो अकाल के समय में इनका काम चल जाता था और किसी को भी कुएं से पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ता था। वर्ष 1995 में, हमारे गुजरात में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बी.जे.पी. की सरकार बनी, तो कल्पसर योजना की प्लानिंग हुई थी खंबात की अखात में एक वॉल बनाकर जो गुजरात की नदियां हैं, उनका मीठा पानी स्टोर किया जाए।

महोदय, करीब पूरे गुजरात को पीने का मीठा पानी और सिंचाई का पानी इससे दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। उस योजना का सर्वे भी हो चुका है। इसलिए माननीय गजेन्द्र सिंह जी से मेरी विनती है कि इसके बारे में आगे कुछ कार्रवाई करें तथा इस कल्पसर योजना को आगे बढ़ाया जाए।

महोदय, इज़रायल में सिर्फ तीन या चार सेंटिमीटर बारिश होती है, लेकिन वहां micro irrigation, drip irrigation और sprinkler irrigation के हिसाब से किसानों को गाइडलाइन्स दी जाती हैं। वहां की गाइडलाइन्स की सहायता लेकर भी हमारे यहां कम पानी से सिंचाई करके खेती-बाड़ी की जाए। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए, तो अच्छा रहेगा।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Firstly, Sir, I thank the Chair for

having taken up this very important topic which concerns all of us. The headlines from every quarter of the media and personal experiences reveal the stark reality that with every passing year water crisis is becoming more and more a serious issue. In cities, we see that we have to resort to water carts and provision of tankers. Secondly, we see that in villages there is migration which is taking place. Farmers are committing suicides. Water sources are drying up. Sir, we also see that there are dead or no crops on parched lands, which were once agricultural lands. Livestocks have to be kept under shelter and they are also dying. There is excessive pumping of water from the ground. There is also contamination of groundwater, especially, in cities where garbage has been dumped and leachate has formed. These are all very serious concerns and, therefore, we need to address this issue on topmost priority. I will not refer to the report which has been tabled by Niti Aayog because a lot of our colleagues have already referred to it but it is a serious fact that two lakh people are already dying every year because of unsafe water. Twenty one major cities would run out of water by next year. Sir, 40 per cent of the country' s population may not have access to water in another ten years. The worst is that by 2050, the lack of water is predicted to lead us to 6 per cent reduction in our GDP.

Sir, I would come straight to the point that what it is that we need to do. Firstly, we sitting here are not experts but we have grassroots contact to understand the stark reality. I would suggest that there are several reports and studies which have been made on this point. Therefore, we need to put it together. We need to invite experts, form a committee, which forms an action plan. Today, the hon. Minister would respond to our speeches but it is very important that we come out with an action plan which I hope the Government takes at the topmost priority.

Secondly, Sir, I want to make four points for rural areas and four points for urban areas. In the rural areas, we need to resort to efficient and sustainable agricultural practices. Just now, Israel has been quoted. Israel is a classic example where with paucity of water they have done wonders and their production is very high. Second point is restriction and regulation on extraction of ground water. Third one is that we need to undertake contour trenching so that water which falls in the rainy season percolates into the ground. Fourthly, for the rural areas, we need to plant a lot of trees so that the root system would ensure rain water harvesting and with all these measures we can restore the degraded land.

For the cities, I want to again make four points. Singapore has been cited and again is a classic example. Sir, all our water bodies have been polluted in all the cities. We need to restore them. We need to make sure that they are healthy once again. Secondly, the development in the urban areas is happening at such a fast pace that it is not sustainable. We cap up the ground with roads. We cap up the buildings with tiles. How does the water percolate into the ground? We have to take certain steps. There are examples in my city,

[Shrimati Vandana Chavan]

Pune but I would not talk about it because of paucity of time. We need to resort to rain water harvesting, incentivize it, give them 10 per cent rebate in property tax but that has to be done with topmost priority. Aquifers need to be mapped. That is my third point because there are so many aquifers which we have to protect. Sir, my on e last pointist that awareness programmes need to be taken up and water conservation has to be taken up. Water metering is absolutely important. Water leakages of pipes in cities, especially, which is almost up to 40 per cent, need to be reduced and water audit needs to be done. Thank you.

डा. डी.पी. वत्स (हरियाणा): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमें इतने important topic - drinking water crisis in the country पर बोलने के लिए परमिशन दी है। सर, हमने farmers suicides तो सुने हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है, जहां पर minimum farmers suicides हैं। But, farmers' murders are quite common and those murders are for water whether it is water for agriculture purposes or water for drinking purposes. Haryana is no exception as the entire nation is reeling under the drinking water and agriculture water crisis. We are also affected by it. Recently, you must have read a report in a newspaper that three villages of Haryana bordering Rajasthan have threatened that they will not take part in Assembly elections if the water crisis rather drinking water crisis is not resolved. I must compliment *Mananiya* Gajendra Singh*ji*, and I do not know as to why they have threatened their villages to be merged with Rajasthan. May be they know now that the Jal Shakti Minister is from Rajasthan! But, they have managed their water well as compared to us. Though our Government has learnt from Israel and we are doing dry-land farming and crop rotations up to an extent that this time the Haryana Government is encouraging the crops which consume less water as compared to paddy.

I will now dilate on the issues which the Prime Minister has suggested in his speech that what we the MPs can do. In Haryana, it is quite customary to distribute drinking water tankers having a capacity of 3,000 and 5,000 litres, motor-fitted. I will request the hon. Minister of Jal Shakti to please do rate contract for मिश्र धातु टैंकर्स with brand new tyres and of good quality because there are rate variations and they are in big demand. We the MPs and as Jatiyaji mentioned that he constructed some small dams, water pumps but the need is water tankers even for hills, desert areas and all villages because in our areas bordering Rajasthan, water is not potable and it is sub-soil water. Now, whatsoever it was, the level has gone down . ...*(Time Bell rings)*... At this stage, if I do not mention the bone of contention between Punjab and Haryana that is going on for the last 40 years because of SYL crisis or SYL litigations ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Dr. Vats.

DR. D.P. VATS: Sir, please.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No; the time is up.

DR. D.P. VATS: About SYL Haryana population thinks now, "आए न तुम सौ-सौ दफ़ा, आए-गए मौसम" and we with the help of Khap Panchayats have resolved many issues like female foeticide. In the same way, we are trying to conserve water. I will again request the Minister of Jal Shakti to involve the village panchayts or the Bhaichara Panchayats or the Khap Panchayats even if the court gives the verdict these will be the panchayts which will assuage the feelings of Punjab masses because water is flowing to Pakistan and flowing to the Arabian Sea. ...*(Time Bell rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Dr. Vats. Please.

DR. D.P. VATS: Till 1966 Haryana was part of Punjab and now, we are their younger brother As a younger brother State, we are beggirng from Punjab that they should give us water for drinking and water for agriculture to maintain *Bhaichara* rathar than letting in how to Pakistan and sea. This will resolve the crisis in addition to the other measures for water conservation and water harvesting which have already been talked about. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you Vice-Chairman, Sir. Sir, the challenge of water crisis is basically on account of monsoon failure and partly because of deforestation. Many Members have suggested that the only solution to this water crisis is linking of rivers. That is the only solution. In this regard, I would like to make some suggestions. The Government of India, earlier, used to sanction one national project to every State and the Government of India, of late, has decided not to continue that process. In lieu of that, it is advisable for the Government of India to fund, at least, two or three projects relating to interlinking of rivers in each State. That is one suggestion. The State of Andhra Pradesh has taken up the linking of Godavari and Penna rivers and the Government of India should come forward and fund the interlinking of Godavari and Penna rivers. The Cabinet Committee on Economic Affairs has recently approved DRIP (Dam Rehabilitation Improvement Project) with an estimated cost of ₹ 3,500 crares. In fact, out of 200 dams that have been identified, under DRIP in various States, not a single dam has been included for A.P. I, therefore, request the Government of India to take up, at least, one or two dams in Andhra Pradesh also. Sir, in March, 2018, eight irrigation projects were taken up under Accelerated Irrigation Benefit Programme and some projects are going on for the last more than ten years. Andhra Pradesh has been requesting to include Veligonda project under AIBP. But Jal Shakti Ministry is not approving this. I request the Government of India to positively consider this. Sir, the last point which I would like to highlight is this. Sir, there are some inter-State projects identified under the National Perspective Plans, which benefit surrounding States such as Mahanadi-Godavari water transfer link, Godavari (lcchampally) and Pulichintala water transfer link, Icchampally and Nagarjunasagar water

[Shri V. Vijayasai Reddy]

link, Almatti and Pennar water transfer link and some other links also. But the problem is that they are not being pushed by the Jal Shakti Ministry. I request the Government of India to take up these inter-State water-linking projects. Sir, my last point is, as per the data of Central Ground Water Board, per capita availability of water has come down from 14,180 litres in 1951 to 5,210 litres in 2001 and this is going to come down further to 3,120 litres by 2050. So this has to be addressed properly. Thank you, Sir.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Now, Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, about two-three decades back when we first heard about the term ' water refugees I none of us were ready to believe it. We know the term ' climate refugees I. But now it has come to our doorsteps. We are facing it today. We have been witnessing people shifting their homes from Chennai, from cities to whichever places where they get water. This is the situation now. Sir, please take note that in this country, in the national capital, two weeks back a cricket stadium was maintained by potable drinking water. The Jal Shakti Mantralaya should take care of this. In a country like India where thousands of people, lakhs of people, crores of people are thirsty for water, cricket stadia are being maintained by potable drinking water. We talk about *vikas, sabka vikas*. What is the meaning of *'vikas'*?

There is also a political agenda behind *Sabka Vikas.* The question is, development for whom and how. These questions are to be addressed. In the present conditions, development is only for the rich and not for the common people. That is a battle in this water trouble. Drinking water should be a basic right, undeniable right, and fundamental right also. In various parts of the country, people are dying. The earlier speaker said that two lakh people died in India due to unsafe drinking water. The other day, I saw in Muzaffarpur, the patients, the kids, their parents who told me that in their villages there is no availability of safe drinking water. Sir, this is India! In this India, where the poor are denied food, water, and basic necessities of life, we talk about our Independence anniversary. Sir, I am concluding by making the following suggestions. The Jal Shakti Mantralaya should take note of it. We should have a comprehensive water management policy. That should include the following points.

(i) Ensure safe drinking water as a fundamental right;

(ii) It should not be a saleable commodity for profits;

(iii) Ensure proper storage of recharging of ground water;

(iv) Ensure rain water harvesting;

(v) Protect sources like rivers, forests, and mountains. That means, protect environment, and that politics to protect the environment is the basic factor where the Government which is careful only about environment protection, should also be careful about water also. With this, Sir, I conclude. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Chunibhai Kanjibhai Gohel.

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो एक गहन विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। सर, गांव में कहा जाता है कि पानी को बचाओगे, तो पानी आपको बचाएगा। सर, एकदम सत्य बात है कि अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे, तो पानी के बगैर हम जी नहीं पाएंगे। पहले तो मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय को अलग किया और दूसरा मछुआरों के लिए Ministry of Fisheries को भी अलग किया। मैं यहां से प्रिय प्रधान मंत्री जा का अभिनन्दन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री जी, जिन्होंने अभी इस मंत्रालय का प्रभार लिया है, यह पानी वाला मंत्रालय है, उनके लिए यह कहा जाएगा कि यह तो पानी वाला मिनिस्टर है। गुजराती में बोलते हैं पानीदार मिनिस्टर है। सर, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मैंने हमारी बहन को भी बताया था कि अगर मेरी टर्न आती है, तो ठीक है, नहीं आती है, तो आप बोलिएगा। आपके आसन पर बैठने पर मेरी टर्न आ गई है।

(श्री उपसभापति *पीठासीन हुए)*

सर, हम लोग गए थे, सरकार ने हम लोगों को सिंगापुर भेजा था। सर, सिंगापुर में रोड पर जितना भी बारिश का पानी गिरता है, वह सारे का सारे का सारा पानी, अगर मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे तो, मेरे ख्याल से उनको भी फायदा होगा। वहां पर हर जगह रोड की बाजू में एक कैनाल बनी हुई है। मैंने पूछा कि यह जो बड़ी कैनाल रखी है, क्या यह गारबेज की है? तो उन्होंने मुझे बताया कि यह जो कैनाल है, जो बारिश का पानी गिरता है, वह पानी रोड से गिर कर सीधे कैनाल में जाएगा और पूरे सिंगापुर के सब गांवों में जब हम घूमे, तो वही कैनाल हमको सब जगह दिखाई दी। उन्होंने यह किया है कि सिंगापुर में जितना भी पानी गिरता है, उसमें मुश्किल से मात्र 10 प्रतिशत पानी समुद्र में जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। आज सिंगापुर में पीने के पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। जब 2016-17 में हम लोग वहां गए थे, तो उनके पास पानी को लेकर 2045 तक की प्लानिंग थी। बाद में उन्होंने बताया कि अभी भी हम पानी के ऊपर पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। जो पानी हमारे यहां पीने का है, वह पानी अलग डैम्स में रखा है, जो पानी लोग यूज़ कर लेते हैं, बाद में फिल्टर करके उसको फैक्टरीज़ में दिया जाता है, फैक्टरी वाले उस पानी को यूज़ करके, वापस उसी पानी को सर्कुलेज करके उस पानी को लोग सफाई के काम में लगा देते हैं। सर, मैं एक बात कहूंगा। गुजरात में 'गुजरात मॉडल' क्यों बोलते हैं, गुजरात आज क्यों आगे हैं? वहां आज हर घर में पानी होता है। अगर मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूं, तो हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने सन् 2000 में जब गुजरात के शासन की बागडोर सम्भाली, तब पानी की बहुत समस्या थी, हर गांव में पानी की प्रॉब्लम थी, हर शहर में पानी की प्रॉब्लम थी। इन्होंने यह तय किया कि अगर पूरे गुजरात को पानी चाहिए, तो वहां जितना पानी गिरता है, वह समुद्र में न जाए, क्योंकि वहां का 80 परसेंट पानी समुद्र में चला जाता था। उन्होंने यह किया कि जितनी भी नहरें हैं, कैनाल्स हैं, सबकी सफाई करवाई, जितने भी डैम्स थे, उन सब डैम्स को आपस में जोड़ दिया। आज

[श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल]

की डेट में पूरे गुजरात में जितने भी डैम्स हैं, वे एक दूसरे से linked up हैं। राजकोट में जो डैम है, अगर वहां पानी कम हो गया, तो ऊपर जो दूसरा डैम है, सीधे वहां से पानी आ जाएगा। नर्मदा का पानी कैनाल द्वारा लोगों तक, किसानों तक पहुंचता है। सर, मैं आपको बताता हूं कि वहां 800 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन बिछायी गयी है और नर्मदा का पानी 800 किलोमीटर दूर स्थित घरों में आता है। उस कैनाल की जो पाइपलाइन है, वह कैसी, मालूम है? पूरी गाड़ी लेकर अगर आप उसमें निकल जायेंगे, एस.यू.वी. लेकर आप अन्दर से जायेंगे, तो वह गाड़ी आराम से 700 किलोमीटर तक चली जायेगी। जब ये यह काम कर रहे थे, तब कांग्रेस के हमारे जो मित्र बैठे थे, उन्होंने कहा था कि नरेन्द्र भाई, आप जो पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, इसमें से हवा आयेगी। लेकिन उसमें से हवा नहीं, सर, उसमें से पानी आया और नरेन्द्र भाई ने वहां के हर घर में वह पानी पहुंचाया। सर, आज मैं आपको बताता हूं कि 2018 से हमारे माननीय मुख्य मंत्री विजय भाई रूपाणी जी जो काम कर रहे हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने यह किया है कि वहां जितने भी डैम्स हैं, उन डैम्स की खुदाई करवाई, कैनाल्स की सफाई करवाई और सबको आपस में जोड़ दिया। सभी NGOs को जोड़ दिया।

श्री उपसभापति: आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करें। उसके बाद मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: सर, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं।

सर, हमारे वहां पानी के ऊपर अभी भी इतना काम चल रहा है कि इनसे हमारे गुजरात में पानी की समस्या बहुत कम है, यह मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से सब राज्य अगर करेंगे, सब राज्यों में यही स्थिति बनेगी, वे यह गुजरात मॉडल अप्लाई करेंगे, तो मैं मानता हूं कि कहीं पानी की समस्या नहीं रहेगी, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जैसा इस चर्चा को प्रारम्भ करते हुए संजय सिंह जी ने कहा और अनेक वक्ताओं ने कहा कि यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं यह मानता हूं कि पानी पूरी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अपने sustainable development goals की श्रृंखला में प्रमुखता के साथ रखा है। निश्चित रूप से यह पूरे विश्व के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है और, ऐसे समसामयिक विषय पर सदन ने चर्चा को स्वीकृत किया। साथ-ही-साथ, मैं आदरणीय संजय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): सर, एक मिनट। Sir, this is a very important subject. But, looking at the presence of Members, I suggest if we can have the Minister's reply tomorrow. Otherwise, at six o'clock, the House gets adjourned.

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आपकी अनुपस्थिति में हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत सारे स्पीकर्स थे। हमने उनको समय दिया। उस वक्त मैंने यह अनुरोध किया था कि हम सबको समय देना चाहते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब पूरा होने तक...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: नहीं, सर। मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Many of us would want to seek clarifications. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, let us have it tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, when I requested you, you already mentioned. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the rule of this House is that the Members have a right to seek clarifications. At six o' clock, the House is to adjourn.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, tomorrow, we also have a Calling Attention Motion on climate change whose notice the Members have given and hon. Chairman has accepted it.

SHRI ANAND SHARMA: It will not take much time.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Also, then, there are Bills listed. So, for tomorrow we will have full Business. Then day after tomorrow is a day for Private Member's Bills. I think, we should complete this today itself.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the sense of the House which I have alreary taken earlier. माननीय आनन्द जी, मैंने पहले बात करके सबसे निवेदन कर लिया।

SHRI T. K. RANGARAJAN: For the benefit of the larger body and the Press also is ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Both the issues are important. Please don't misunderstand us. What is important is that those Members who have unfortunately left today, because yesterday and the day before we sat late, we have been accommodating.

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, मैंने आपकी बात समझ ली है। आपके आने से पहले मैं निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सभापति महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि इस बहस को ढाई घंटे में complete करना है। I had already intimated. इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे complete होने दें।

श्री आनन्द शर्मा: 6 बजे के बाद हाउस तय करेगा कि हमने बैठना है या नहीं बैठना।...**(व्यवधान)**...हम रोज़ तो लेट नहीं बैठ सकते।

श्री उपसभापति: यह निवेदन मैं पहले कर चुका हूं, तभी बाकी माननीय सदस्यों को समय दिया गया है। Rajaji, I had requested you. It is on record. ...*(Interruptions)*... Please continue, Mr. Minister.

SHRI D. RAJA: It is an important issue. The whole House can listen to the Minister. It is for the good of the Minister that we are saying. ...*(Interruptions)*...

6.00 P.M.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय संजय सिंह जी का, जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को सदन में आमंत्रित किया है। यह दीगर बात है कि चर्चा प्रारम्भ करने के 5 मिनट बाद ही शायद उनके लिए यह विषय महत्वपूर्ण नहीं रहा। चर्चा के अभिलेख में उन्होंने देश की जल समस्या पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी, लेकिन जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जैसा मैंने पाया, वे केवल दिल्ली तक ही सीमित रहे। मुझे लगता है कि उनके लिए देश दिल्ली तक ही सीमित है।

मैं यहां सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं - आदरणीय संजय सिंह जी, डा. सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय अमी यज्ञिक जी, आदरणीय मानस रंजन भूनिया जी, आदरणीय रवि प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय कहकशां परवीन जी, आदरणीय डा. बांडा प्रकाश जी, आदरणीय प्रशांत नन्दा जी, आदरणीय टी. के. रंगराजन जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, अनिल देसाई साहब, डी. राजा साहब, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर साहब, आदरणीय हुसैन दलवई जी, विशम्भर प्रसाद निषाद जी, आर.एस. भारती जी, डा. अशोक बाजपेयी जी, श्री अशोक सिद्धार्थ जी, श्री लाल सिंह वड़ोदिया जी, श्रीमती वंदना चव्हाण जी, डा. डी. पी. वत्स जी, श्री वि. विजयसाई रेड्डी साहब, श्री बिनोय विश्वम जी, श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल जी और अन्य सदस्यगण - जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यहां जो सुझाव दिए और अपनी चिन्ता व्यक्त की, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें इस विषय पर चिन्तन और योजनाओं के निर्माण में योगदान मिलेगा।

मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, उससे पहले जितने वक्ताओं ने इस विषय पर चर्चा की, उनमें प्रमुख रूप से श्री अनिल देसाई साहब का मैं हृदय से बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूं। जिन 26 लोगों ने यहां अपने विचार व्यक्त किए, उनमें से वे केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि यदि जल से जीवन को सुरक्षित करना है तो हमें इसकी शुरुआत अपने आपसे करनी होगी। जब हम अपने आपसे इसकी शुरुआत करेंगे तभी हमारा जीवन जल को लेकर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है। जब हर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझेगा, तभी यह सुरक्षा हमें प्राप्त हो सकती है। केवल सरकार के भरोसे या सरकारों पर छोड़ देने से कभी भी हम आने वाली पीढ़ियों को जल सुरक्षा नहीं दे पाएंगे।

महोदय, यहां अनेक माननीय सदस्यों ने जिस बात पर जोर दिया, उसके अनुसार हमारे देश में दुनिया भर की केवल ढाई प्रतिशत ज़मीन है। दुनिया में जितना potable water है, out of that, केवल 4 प्रतिशत हमारे यहां है, जबकि पूरी दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या और लगभग 22 प्रतिशत livestock population भारत में है। इस दृष्टिकोण से, निश्चित रूप से जिस तरह की चिन्ता सभी माननीय सदस्यों ने यहां व्यक्त की, वह चिन्ता अत्यंत जायज़ है। जैसा माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में इस बात को कहा, मुझे लगता है कि शायद कुछ सदस्यों की बातचीत की समझ में कहीं थोड़ा-बहुत फर्क रह गया था कि देश में 4,000 बी.सी.एम. पानी कुल मिला करके हर साल हमको उपलब्ध होता है।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी... माननीय सदस्यों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पहले जैसी मैंने सूचना दी थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनेक ऐसे स्पीकर्स के नाम आए, जिनका नाम पहले नहीं था। हमने आपसे आग्रह किया कि इन सबको accommodate करके हम लोग इनको इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दे रहे हैं और यह आग्रह आप लोगों के बीच से ही आया था।

इसके बाद मिनिस्टर reply करेंगे, otherwise हम साढ़े पांच बजे conclude करते और मंत्री जी इस पर जवाब देते। आप सबने उस वक्त सहमति दी थी। अब मैं चाहूंगा कि हाउस इस बारे में पुन: निर्णय करे कि अब क्या करना है?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, this is a very important and critical subject that we are discussing and almost all the hon. Members of the House expressed their views. The hon. Minister is giving his reply now. I suggest that till the reply is concluded, the time of the House may be extended.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Then, we can take up Special Mentions.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति जी, देश में वर्ष में जो कुल मिला करके 4,000 बी.सी.एम. पानी वर्षा के माध्यम से उपलब्ध होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमको मिलता है, उस 4,000 बी.सी.एम. पानी में से, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि runoff और evaporation के बाद कुल मिला करके हमारे पास 1,137 बी.सी.एम. पानी उपभोग के लिए बचता है। इस 1,137 बी.सी.एम. पानी में से जो सतह पर बहने वाला जल है, वह लगभग 690 बी.सी.एम. है और इसके अतिरिक्त जो भूगर्भ में जल, replenishable water, जो हर साल आता है, जिसके बारे में लगभग सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, वह लगभग 447 बी.सी.एम. है। हम सबको इस बात की जानकारी है, हम सबने इस बात के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है कि यह जो 447 बी.सी.एम. पानी, जो हर साल वापस replenish होता है, लेकिन हम इससे कहीं अधिक ज्यादा दोहन इस भूगर्भ के जल का कर रहे हैं। मैं सारे सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक राय हो करके इस बात के लिए सहमति व्यक्त की है, सबने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की है और सरकार से आग्रह किया है कि इस भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए व्यापक और विशेष योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इस समय मैं एक धन्यवाद और करना चाहता हूं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर साहब का कि उन्होंने स्वयं का उदाहरण दे करके कहा, मैंने उसका साक्षात दृष्टांग खुद देखा है। यदि मैं उर्दू में बोलूं, तो मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। सर, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैंने खुद वहां खड़े होकर देखा है कि किस तरह से उनके खेत में उन्होंने जल संचय और जल प्रबंधन किया है। इससे वे खुद की ज़मीन पर तो सिंचाई करते ही हैं, आस-पास में रहने वाले छोटे किसानों को भी अपने जल संचय से खेती करने योग्य जल उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का समाज और व्यवस्था, दोनों को अभिनंदन करना चाहिए। जब तक इस देश में यह अभिनंदन करने की परंपरा नहीं बनेगी कि हम जल के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, देश भर में बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं, उन सबका सम्मान करें और उन सबको भगीरथ की तरह समाज में प्रतिष्ठा दिलाएं। मैं यह चाहता हूं कि हम सब, जो इस सदन में बैठे हैं, जो निश्चित रूप से समाज को पूरे देश में कहीं-न-कहीं लीडरशिप प्रदान करते हैं, हम सबको संकल्प ले करके इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम देश के ऐसे भगीरथों का सम्मान करना प्रारंभ करें ताकि समाज उनसे प्रेरणा ले सके।

महोदय, चर्चा में यह भी उल्लेख आया था कि देश की प्रति वर्ष जो कुल प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है, per capita water availability, वह 1951 में 5,177 cubic meters थी, 2011 में वह अब घट करके 1,545 cubic meters बच गई। अब हमारे पास लगभग एक-तिहाई से कम जल प्रति व्यक्ति बचा है। लेकिन यदि मैं इसे दूसरी तरह से देखूं, तो जो सन् 1951 में जल की उपलब्धता, जल का संचय और जल की कुल उपलब्धता होती थी, अब भी परिस्थिति लगभग वही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा

[श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत]

परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन देश की जनसंख्या सन् 1951 के बाद तीन गुना बढ़ी है, यह उसका परिणाम है कि देश आज जल के इस संकट से जूझ रहा है, जल का यह संकट हमारे सामने खड़ा है। If I specifically speak for this year, मानसून वर्ष 2018 में नौ प्रतिशत कम था, हालांकि हमारा मानसून पिछले 18 सालों में से 13 साल औसत से नीचे के स्तर पर रहा है। हमने कहीं-न-कहीं कमी दर्ज की है। इस साल मानसून सामान्य तिथि से 15 दिन देरी से चल रहा है। एक जून तक जितनी बारिश देश में होती है, इस वर्ष उससे लगभग 43 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस कारण से, देश के कुछ हिस्से, जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्णाटक, केरल और तमिलनाडु ऐसे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, हमने देश में भूगर्भ के जल की भी चिंता की, जो प्रत्यक्षत: बरसात के पानी से जुड़ा हुआ है। भूगर्भ के जल का स्तर भी अत्यधिक दोहन के कारण से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ में drastically बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन इस सब के अतिरिक्त देश में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस भूगर्भ के जल की चिंता की। मैं सम्मान के साथ महाराष्ट्र और जिस प्रदेश से मैं आता हूं, राजस्थान का उल्लेख करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। इन दोनों प्रदेशों ने अपने यहां कार्यक्रम लिया, वह अन्य प्रदेशों ने भी लिया है। कर्णाटक के मित्रों ने भी अभी उसके बारे में चर्चा की, Mission Kakatiya की चर्चा की, Neerukattu की चर्चा की, लेकिन इन दोनों प्रदेशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के साथ-साथ वर्षा से आने वाले जल के संचय के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस गंभीरता से काम किया है, उसका परिणाम है कि ये दोनों प्रदेश, जो पहले most vulnerable State की कैटेगरी में आते थे, वे दोनों ही water balance State की कैटेगरी में प्रमोट हो गए। मैं यह मानता हूं। आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देश भर का प्रतिनिधित्व करने वाले, देश भर का मार्गदर्शन करने वाले लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर रहा हूं, ऐसे सदन के बीच खड़े होकर बात कर रहा हूं, हम सभी को अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह से जल का प्रबंधन हो, इसमें भागीदारी और लीडरशिप लेकर करने की आवश्यकता है। हम सब ने re-use of water की विस्तार से बात की और लगभग सभी सदस्यों ने black water और grey water के re-use के बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मैं यह मानता हूं कि यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, पेयजल सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन देश में जो कुल जल का उपभोग होता है, उसमें केवल पांच प्रतिशत हिस्सा ही पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है, लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा industrial water के रूप में use होता है और बाकी शेष बचे पानी का 80 प्रतिशत हिस्सा कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है। मुझे सौभाग्य से मोदी जी की पिछली सरकार में कृषि के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला था। मैं खुद कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। मुझे प्रत्यक्षत: हाथ से हल चलाने का और खेत में काम करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। देश में फसलों के लिए पानी का उपयोग जिस तरह से होता है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। यदि मैं केवल चावल के विषय में बात करूं, तो आज भारत में जो औसत एक किलो चावल पैदा किया जाता है, उसके लिए 5,600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आप सब लोग कॉटन का जो एक कुर्ता पहनते हैं, उस एक कॉटन के कुर्ते को बनाने के लिए लगभग 5,000 लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग होता है। आप इस राज्य सभा में जो एक कागज़ पर लिखते हैं, इस कागज़ के ऊपर...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I have a point of order. It is not

understood whether you mean to say the entire crop or one *kurta*.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I am saying 'one *kurta*'. One *kurta* requires 5,600 litres.

SHRI ANAND SHARMA: What is this? I have been the Textiles Minister of this country also. This is not correct. Kindly check your facts, because it could be for a particular acreage of land, whether for paddy or whether for cotton. It cannot be for one *kurta* or it cannot be for one kilogram or rice.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय आनन्द जी, मैं जो कुर्ते की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अभी आपके जितना अनुभवी नहीं हूं, इसलिए आपको नहीं समझा पाया हूं। आपका कुर्ता बनाने में जितना कॉटन कुल मिलाकर उपयोग हुआ है, उतना कॉटन पैदा करने में इतने पानी की आवश्यकता होती है, यह मैं आपसे कहना चाहता था।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: As we understand, this much of water is required for the entire crop and not to make one *kurta*.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: साहब, मैंने जैसा कहा, मैं गांव का आदमी हूं। मैं एक किसान हूं और मैं किसान की बुद्धि जितनी बात कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री भुवनेश्वर कालिता: हम भी गांव के हैं, हम भी खेती से जुड़े हुए हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: कॉटन पैदा करने के लिए कुल मिलाकर जितना पानी उपयोग होता है, उसका औसत निकालकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह हो सकता है कि आपका कुर्ता दुनिया में किसी दूसरे देश, शायद स्विट्ज़रलैंड से आए हुए कॉटन से बना हुआ होगा, इसलिए मेरी बात से आपकी सहमति नहीं है।...**(व्यवधान)**...

माननीय उपसभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कागज़ का एक टुकड़ा... शायद ये फिर मेरी बात से असहमति व्यक्त करें,... एक कागज़ का पुर्जा बनाने में भी कुल मिलाकर लगभग 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। खेती के लिए पानी का जो उपयोग है, ठीक उसी तरह से चावल के लिए अगर मैं दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जिसके संबंध में मैंने कहा कि एक किलो चावल पैदा करने में 5,600 लीटर पानी की जरूरत होती है, तो चीन में एक किलो चावल पैदा करने के लिए पानी की कुल मिलाकर लागत 350 लीटर है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तकनीक नहीं है, हमारे यहां उस तरह का पौध नहीं है, उस तरह की प्रजातियां नहीं है या हम उन्हें विकसित नहीं कर सकते हैं। हमारे यहां उसके लिए कुल मिलाकर जिस स्तर की sincerity होनी चाहिए और प्रदेशों के माध्यम से जिस तरह के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि कृषि प्रदेश का विषय है, उसमें कहीं-न-कहीं कमी है और हम सबको उस बारे में भी विचार और चिन्ता करने की आवश्यकता है।

जब मैंने इस बात की चर्चा की है, तो मैं हरियाणा की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हरियाणा की सरकार ने पानी बचाने के उद्देश्य से चावल पैदा करने वाले किसानों को incentivise करके उनको प्रति एकड़ 2,000 रुपये देने की योजना बनाई है, ताकि वे चावल की जगह दूसरी alternative crops पैदा करें। वे जो alternative crops पैदा करें, उस क्रॉप को वे 100 प्रतिशत एम.एस.पी. दर पर खरीदेंगे, इसकी गारंटी भी हरियाणा की सरकार ने दी है। इस तरह की पहल सब

[श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत]

प्रदेशों में करने की आवश्यकता है।

मैं यहां महाराष्ट्र का भी उल्लेख करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में खेती में कुल मिलाकर जितने पानी का वर्ष भर में उपयोग होता है या महाराष्ट्र का हरेक किसान मिलकर जितने पानी का उपयोग करता है, उसका 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी केवल गन्ने का किसान गन्ना उगाने के लिए उपयोग करता है। मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि महाराष्ट्र में गन्ने का किसान अब केवल और केवल drip irrigation के माध्यम से ही गन्ने की सिंचाई कर सकेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे कृषि मंत्रालय में काम करने का सौभाग्य मिला। जिस तरह की साइंटिफिक रिपोर्ट्स इसमें आई हैं, वे रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि यदि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो गन्ने में जो शूगर कंटेंट है, वह 24 परसेंट बढ़ता है। हम सबको मिलकर अपने-अपने प्रदेशों में इस तरह की पहल करने की आवश्यकता है। मैंने ये दो उदाहरण दिए हैं, हो सकता है कि इसके अतिरिक्त भी प्रदेशों में कहीं न कहीं इस विषय पर इसी तरह से विचार और चिंतन हो रहा होगा, लेकिन इसको गति देकर और तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रो, सतही और भूमिगत संसाधनों के समग्र प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना बनाने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधान मंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। देश में पानी का विषय, जिसकी महत्ता की चर्चा आप सबने की, वह आज़ादी से लेकर अब तक अनेक मंत्रालयों में, अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग रूप में, अलग-अलग दृष्टिकोण से उसके बारे में विचार, चिंतन और पॉलिसी प्लानिंग की जाती थी। इरिगेशन किसी और मंत्रालय में देखा जाता था, रूरल ड्रिंकिंग वॉटर की कहीं और विषय पर चर्चा की जाती थी, अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर कहीं और था और वॉटर शैड कहीं और था। सबको एक जगह मिलाकर यह प्रयास किया गया है कि सारे ड्रिंकिंग वॉटर, जल से लेकर सारे विषय एक ही छत के नीचे, एक साथ होलिस्टिक मैनर में, इंटिग्रेटेड मैनर में एक साथ उसका चिंतन और प्रबन्धन किया जाए। इस देश में यह एक नई शुरुआत हुई है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया है। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। आसन ने अभी जिस नाम का उल्लेख किया था, अनुपम मिश्रा जी और रजत जी का उल्लेख किया, उन्होंने जो चर्चा की थी, मैंने अनुपम मिश्रा जी की किताब को पढ़ा है और माननीय अनुपम मिश्रा जी ने इस विषय पर टेड टॉक दिया था, वह भी मैंने देखा है। उन्होंने जो जल प्रबंधन की उत्तम नीतियों के बारे में बताया है, जो हमारे यहां पौराणिक काल से थीं, उनमें से उन्होंने कुल 22 विषय लिए हैं और टेड टॉक में 6 विषय लिए हैं, वे 6 मेरे प्रदेश, राजस्थान से आते हैं।

अभी ओम प्रकाश माथुर साहब बता रहे थे कि जिस तरह से बरसात की छत पर गिरने वाली हर एक बूंद को अमृत की तरह संचय करते हुए एक-एक बूंद का उपभोग और उसको सुरक्षित, संरक्षित करके वर्षपर्यन्त पीने के लिए मैंने स्वयं अपना बचपन उसी तरह से गुज़ारा है। आज भी मेरे घर में, गांव में पीने का पानी, जो बरसात का पानी साल भर में एकत्रित होता है, जो साल भर 30-40 हज़ार लीटर का एक टैंक में, एक छत से पानी एकत्रित होता है। मेरे गांव में कुल मिलाकर साल में 200 एम.एम. भी बरसात नहीं होती। मैं सबसे कम बरसात वाले जिले जैसलमेर से आता हूं। वहां अगर 200 एम.एम. या उससे कम बरसात होती है तो साल भर पीने के पानी की सुरक्षा हमारे परिवार को मिलती है। इस तरह से हर एक घर self-sustainable है, लेकिन यह जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, अभी किसी वक्ता ने उल्लेख किया कि भारत जैसे देश में, जहां जल को जगदीश मानने की परम्परा थी। भारत जैसे देश में जहां वरुण देवता की पहले प्रथम आराध्य गणेश जी के बाद में, पहली पूजा की गई, नदियों को देवी

मानकर उसकी आराधना की गई, उस देश में दुर्भाग्य से आज हमारी यह स्थिति है कि दुनिया का सबसे contaminated water deposit कहीं अगर है, तो भारत में है। पिछले 40-50 साल, 100 साल में ही ये परिस्थितियां क्यों हुई? मुझे याद है, मेरे बचपन में गांव में 4-5 चीज़ें, जो इन सारे विषयों को एक साथ जोड़ती थी, ऐसे 4-5 विषयों को बिना किसी कानून के, बिना किसी लिखित व्यवस्था के, उसको पूरा गांव और समाज एक साथ मिलकर संरक्षित करता था। पहला जो तालाब का कैचमेंट था, उसकी तरफ, उसकी पवित्रता बनी रहे, इसकी चिंता गांव का प्रत्येक व्यक्ति करता था, उसके बारे में कमिटमेंट के साथ, conviction के साथ काम करता था। गांव का जो जंगल है, अरण्य है, उसमें से दातुन करने के लिए कोई लकड़ी नहीं तोड़ता था, इस तरह की शुचिता बनाये रखने की परम्परा थी। गांव का जो गौचर है, गांव में जो पशुओं के चरने की ज़मीन है, उस ज़मीन पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो, किसी भी तरह का क्षरण न हो, उसके लिए पूरा गांव समर्पित भाव से साल में एक दिन अरण्य के नाम पर, साल में एक नियत दिन पर श्रमदान करता था। ऐसी परंपरा गांव में थी। पूरा गांव साल में एक बार जाकर तालाब की पूजा करता था। समुद्र मंथन उसका नाम था और पूरा गांव उसको उत्सव के रूप में मनाता था। ऐसी समृद्ध परंपरा जिस देश में थी, 50 साल में जिस तरह से पिछली एक पीढ़ी में जिस तरह से ...**(व्यवधान)**...

श्री भुवनेश्वर कालिता: हम यहां कहानी सुनने नहीं आए हैं। ...**(व्यवधान)**... जो प्वाइंट्स हैं, आप उन पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप तो कहानी सुना रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं आपके सारे प्वाइंट्स पर आता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भुवनेश्वर कालिता: आप कहां पैदा हुए? कहां पर आपकी परवरिश हुई? आपने कहां पानी पिया? हम सब यह नहीं जानना चाहते हैं। हमने जो प्वाइंट्स बताए हैं, उनका reply दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं जिस तरह से सब लोगों ने जिस गंभीरता के साथ चिंता व्यक्त की है और इस विषय के ऊपर चर्चा की है, हमें यह ढूंढना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि इस समस्या की जड़ कहां है और जब तक जड़ नहीं जानेंगे, तब तक इलाज नहीं हो सकता है। हम फौरी तौर पर सरकार की तरफ, जब तक इसके निमित्त देखते रहेंगे, तब तक इस विषय का समाधान नहीं हो सकता है। हमें अपने आपको उसके बीच में खड़ा करके देखना पड़ेगा कि कहां हमारी पीढ़ी से चूक हुई है। आनन्द शर्मा जी, मेरे पिताजी की उम्र के हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: आपकी आयु कितने वर्ष है? ...**(व्यवधान)**...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मेरी आयु 50 वर्ष है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मैं आपसे 15 साल बड़ा हूं। ...**(व्यवधान)**... आप क्या बात कह रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मेरे पिताजी से चार-पांच साल ही छोटे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, इस बारे में माननीय आनन्द जी जो कहेंगे, वह सही है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: वैसे भी जो आनन्द जी कहेंगे, वह ही सही है। मैं यह मानकर चलता हूं।

श्री उपसभापति: आनन्द जी, हम सब यही चाहते हैं कि आप युवा रहें और इसी तरह आपका...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति जी, मैंने कुछ विषयों की चर्चा की, उसके साथ में एक विषय जो मेरे घर-परिवार में जो संस्कार में सिखाया था, वह यह था कि ब्राह्मण का बेटा तो चार साल का भी हो वह दादा के बराबर है, इसलिए कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is not. ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, this is not. ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपने संस्कारों की चर्चा कर रहा था। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, यह castiest expression है।...**(व्यवधान)**... सर, दुनिया में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपकी बात भी रिकॉर्ड पर आ गई। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): SIr, please allow me for a minute. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMEAN: Please, please. ...*(Interruptions)*... You are left with only six minutes. You have to complete within half an hour. ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि मैं इन परंपराओं की चर्चा कर रहा था, जिनके कारण जल की सुरक्षा समाज को मिलती थी। यदि उन परंपराओं को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उन सारे विषयों को संरक्षित, उन सारे जल संसाधनों का जो पौराणिक रूप से हमारे पास थे, उन सब को यदि हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जैसा आप सभी लोगों ने चर्चा की थी, तो हम शायद जल से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं ये सब विषय आपके सामने रखना चाहता था कि जिस तरह से एक-एक बूंद पानी का संरक्षण करने की समृद्ध परंपराएं थीं, उन परंपराओं को हमने कहां खोया है? क्यों हमारी पीढ़ी ने जिस तरह से पारंपरिक रूप से यह पीढ़ी दर पीढ़ी, यह ज्ञान, यह विदा, यह संस्कार, जिस तरह से हस्तांतरित होते थे, उस हस्तांतरण में कहां चूक हुई है, उस बात को हमें खोजना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... माननीय उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**... जल शक्ति मंत्रालय ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अन्य कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आपकी बात ही रिकॉर्ड में आएगी।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अभी हमने जल शक्ति मंत्रालय की चर्चा की है। उसी के अनुक्रम में यदि मैं बात करूं, तो माननीय सदस्यों ने अपेक्षा की थी कि राज्यों का सहयोग लेकर, राज्यों को साथ लेकर और जल शक्ति मंत्रालय को विशेष रूप से पेयजल की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। पदभार ग्रहण करने के बाद सातवें दिन से देश के सारे जल संसाधनों से जुड़े हुए विषयों को देखने वाले सारे मंत्रियों को एक साथ बैठाकर, चाहे वे पेयजल से जुड़े हुए विषय को देखने वाले प्रदेश में मंत्री हों... चाहे वे irrigation को देखने वाले मंत्री हों या स्वच्छता को देखने वाले मंत्री हों - इन तीनों विषयों को देखने

वाले मंत्रियों और अधिकारियों को एक साथ बिठाकर हमने पूरे दिन की वर्कशॉप की कि उन्हें भारत सरकार से क्या अपेक्षा है और हम किस तरह से उनके साथ मिलकर - माननीय मोदी जी ने जो Cooperative Federalism का नारा दिया है, इसको साथ लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिस मिशन को लेकर हम चले हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी ने जिस बात की घोषणा की है कि हम 2024 तक प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करेंगे, इस संकल्प को हम साथ में लेकर चलें। अनेक सदस्यों ने इस बात की चिंता व्यक्त की, मेरे एक मित्र इस बात की चर्चा कर रहे थे और वे यह कह रहे थे कि कहीं देश में पिछली सरकार के समय में हुए जुमलों जैसा न हो जाए।

SHRI T.K.S. ELANGOVAN: What about linking of rivers? ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: पूरा देश विश्वास करता है कि जिस तरह से घर बनाने की बात की थी, गैस का चूल्हा देने की बात की थी, शौचालय बनाने की बात की थी और उन विषयों को जिस तरह से हमने 100 प्रतिशत के साथ, जिस commitment के साथ पूरा किया है, अब पूरे देश में उस पर मुहर लगाकर हमें भेजा है, पूरे देश ने पहले से बड़ा mandate इसी विश्वास के नाम पर देकर भेजा है। पूरा देश इस विषय को विश्वास के साथ मानता है, पूरा देश आज इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी है तो मुमकिन है और माननीय मोदी जी ने यदि कहा है कि हम देश के प्रत्येक घर को पानी पहुंचाएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह ही कहा था कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग मुद्दों को solve करने की बात करें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mandate is given ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएंगे। ...**(व्यवधान)**... हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री उपसभापति: आधा घंटा पूरा होने में आपके पास दो मिनट का वक्त बचा है। आपको आधे घंटे में जवाब देना था, जिसमें से सिर्फ दो मिनट बाकी बचे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति जी, मेरे मित्र मनोज कुमार झा जी बैठे हैं। मनोज कुमार झा जी जब अपनी बात कर रहे थे, तब इन्होंने कहा कि शंघाई मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि लंदन का मॉडल भी इस देश में नहीं चल सकता है। बहुत सारे मित्रों ने सिंगापुर के मॉडल की बात भी की है। मैंने सिंगापुर के मॉडल को बहुत करीब से, बहुत अच्छी तरह से देखा है और मैंने आस्ट्रेलिया के मॉडल को वहां रहकर अध्ययन किया है, वहां पर पढ़ाई करके देखा है। आस्ट्रेलिया के water management को firsthand वहां बैठकर, उस institute में बैठकर पढ़ा है, लेकिन मनोज कुमार जी, इस देश में कोई मॉडल अगर चलेगा तो वह मोदी मॉडल चलेगा और मोदी मॉडल यह है कि हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, Short-Duration Discussion should be of short duration. ...*(Interruptions)*... This is of long duration. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I seek your protection. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: What is Modi model? ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने की जो बात हम कर रहे हैं, उसके साथ में जो विषय हमने लिए हैं ...**(व्यवधान)**... कि हम केवल पानी पहुंचाने के लिए sources creation की बात नहीं करेंगे, हम पानी पहुंचाने के लिए जो sources create करेंगे, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपके पास एक मिनट का समय है।...**(व्यवधान)**...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: साथ-साथ उन sources की sustainability की भी चिंता करेंगे और उन sources की sustainability के साथ जो पानी निकले ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात खत्म करें।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I am on a point of order ...*(Interruptions)*... Sir, point of order is under our Rules. It is a Short Duration Discussion. The debate on the Motion of Thanks on the President's Address has ended with the Prime Minister's speech. After that, we cannot have a Minister restarting from where the Prime Minister left. Please have a mercy on this House. Follow the Rules Book. It is very clear on the Short Duration Discussion. 'मोदी मॉडल और मुमकिन है', वह Short Duration Discussion का subject नहीं है, water scarcity का है। उस पर खत्म करवाइए, हमें सब मालूम है कि जिस परम्परा का इंतजार था, वह आ गयी है।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द शर्मा जी, आपके कहने से पहले मैंने निवेदन कर दिया था और आपको पहले से पता होगा, लेकिन इसकी सूचना मुझे अभी मिल रही है। वह वहां आया होगा, मुझे पता नहीं है, यह मैंने शुरू में कहा था।

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदय, मेरा एक point of order है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No point of order ...*(Interruptions)*...

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय आनन्द शर्मा जी, मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा था कि यह President's Address में आ गया है, मैं तो conviction की बात कर रहा था कि मुमकिन है।

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हो गया है, कृपया समाप्त करें।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यह जो घर-घर तक जल पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं, इसमें source sustainability साथ-साथ बने, इसकी चिंता भी हम कर रहे हैं और साथ-ही-साथ सभी माननीय सदस्यों ने जिस बात की चर्चा की कि जो grey water निकलता है, उसकी भी चिंता करें ताकि उससे जल पुनर्भरण भी हो सके या recycled water का उपयोग हो सके। इसके साथ-ही साथ हम इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि जो पानी उपभोग के बाद उत्सर्जित होता है, उस पानी का किस तरह से rational उपयोग किया जा सकता है। पानी का विषय निश्चित रूप से चिंता का विषय है, जैसा मैंने कहा कि यह विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। हम सब लोगों को भी इसमें commitment के साथ, एक साथ आना पड़ेगा। मैं सारे माननीय सांसदों से इस बात का आग्रह करता हूं कि आपने अपने-अपने MPLADS Funds में से भी, जिस प्रमुखता के साथ इस विषय में चिंता व्यक्त की है, उतनी ही चिंता व्यक्त करते हुए आपको अपने क्षेत्र में इस विषय से और जल पुनर्भरण के विषय से जुड़ना चाहिए। सरकार की सहायता से 17 लाख से ज्यादा structures

पिछले तीन साल में बनाए गए हैं। सरकार ने इस विषय में 27 हजार करोड़ रुपया खर्च किया होगा, लेकिन हम सब को भी इसमें अपना अंशदान करना सुनिश्चित करना पड़ेगा और जैसा मैंने अनिल देसाई जी के अभिनंदन के साथ में बात प्रारंभ की थी, मैं पुन: उनका अभिनंदन करते हुए इस बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आज इस चर्चा से हम सब लोगों के मन भी यह भाव जाग्रह हो कि हम सभी व्यक्तिगत रूप से commited होकर, जैसे कि माननीय ओम प्रकाश माथुर साहब कर रहे हैं, हम सब लोग भी अपने commitment के साथ, आज यहां से संकल्प करके जाएं कि इस देश में जल संरक्षण में हम सब भी अपना योगदान करेंगे। आप सबका बहुत सारा आभार।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Message from Lok Sabha, Secretary-General. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... Sir, please read Rule 177. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. Let him read, and then I will come to the point to order.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th June, 2019."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I must tell you that the entire House, -- Sir, I need your attention, I need the attention of the House -- I must compliment, the entire House spoke wonderfully, raising important issues with regard to water crisis. Hon. Minister, Sir, you are heading a new Ministry, we expected you to speak with scientific temper, on the basis of scientific evidence. Elections are over, as our hon. Chairperson has said. You, in fact, spoke as if you are speaking on President' s Address. Sir, please come out of election mode. You are heading a very important Ministry. I told you in a lighter way कि आप नमाज...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: धन्यवाद, मनोज जी। Now, Special Mentions. Shri K.C. Ramamurthy.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Yes, Sir.